वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

डा. आर.एस.टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

डा. आर. एस. टोलिया,
भूतपूर्व मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड/
मुख्य सूचना आयुक्त
एवं
महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन
अकादमी, नैनीताल

Our Vision

"To become a self-sustaining, proactive and leading organisation-offering quality capacity building (training and advisory) service in the field of public administration and development initiatives in a competitive environment"

हमारी संकल्पना

''हम लोक प्रशासन एवं विकास में संलग्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों के क्षमता विकास के क्षेत्र में (प्रशिक्षण एवं परामर्श) सेवाएँ प्रदान करने वाली एक आत्मनिर्भर, अग्रणी एवं उत्कृष्ट संस्था बनने की संकल्पना करते हैं।''

Our Mission

"We work for the capacity building of civil servants, Professionals development functionaries and elected people's representatives"

हमारा ध्येय

''हम लोक सेवकों, व्यावसायिकों, विकास कार्मिकों एवं जन–प्रतिनिधियों में कुशल कार्य निष्पादन हेतु क्षमता विकास का कार्य करते हैं।''

प्राक्कथन एवं आभार

डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा 'डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल' को राज्य के शीर्षस्थ संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान समय में, अकादमी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में प्रशिक्षण के माध्यम से गुणवत्ता विकास हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि, उत्तराखण्ड शासन की प्राथमिकताओं एवं जनसामान्य की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु, उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कार्यरत् अधिकारियों एवं कार्मिकों को दक्ष बनाने के उद्देश्य के साथ, अकादमी में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों व अन्य गतिविधियों में तद्नुसार परिवर्तन किए जाने के प्रयास अकादमी स्तर पर किये जा रहे हैं, जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और सार्थक बनाया जा सके। इसी क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के परिवीक्षाधीन आई0ए0एस0 अधिकारियों हेतु ***'सत्रहवाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम'*** तथा उत्तराखण्ड राज्य के परिवीक्षाधीन पी0सी0एस0 अधिकारियों हेतु ***'चौदहवाँ आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम'*** सन्दर्भित वर्ष में आयोजित किया गया।

राजपत्रित श्रेणी के अंतर्गत अकादमी में आयोजित किए जाने वाले सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संदर्भ में आलोच्य वर्ष में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों हेतु ***इकतालीसवाँ सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम,*** सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत् सहायक अभियंताओं हेतु ***बयालीसवाँ सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम*** सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अराजपत्रित श्रेणी के अंतर्गत उत्तराखण्ड सचिवालय में नवनियुक्त समीक्षा अधिकारियों/सहायक समीक्षा अधिकारियों हेतु ***उनतालीसवाँ, चालीसवाँ एवं इकतालीसवाँ सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम,*** परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड में नवनियुक्त परिवहन कर अधिकारी–2 हेतु ***बयालीसवाँ सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम*** तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में नवनियुक्त समीक्षा अधिकारियों/सहायक समीक्षा अधिकारियों हेतु ***तैंतालीसवाँ सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम*** आयोजित किया गया।

उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के समूह 'ख' तथा 'ग' के समस्त ऐसे अधिकारियों/कार्मिकों जिनके द्वारा सेवा में प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का सेवा प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है के लिए एक माह का अनिवार्य सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पूर्व से सेवारत् अधिकारियों/कार्मिकों हेतु मिड कैरियर प्रशिक्षण उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से आयोजित किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या : 450/ XXX (2)/2014,दिनाँक : 3 नवम्बर, 2014 के संदर्भ में सेवा प्रवेश प्रशिक्षण तथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु अकादमी निरन्तर प्रयासरत् है। अकादमी की यह पहल राष्ट्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है।

डॉ आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ का कार्य मुख्यतः दैवीय आपदाओं के सम्बन्ध में सूचनाओं का संकलन, डॉक्यूमेंटेशन, आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में एक्शन प्लान का निर्धारण,पूर्व तैयारी, जागरुकता तथा प्रशिक्षण,कन्सलटेन्सी,शोध तथा क्षमता विकास इत्यादि का कार्य है। डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स अकादमी के मार्ग निर्देशन में सुशासन एवं सतत् विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण,

अनुसंधान एवं परामर्श सेवायें प्रदान करने का कार्य करता है। अपनी क्षमता निर्माण सेवाओं के रूप में सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स अकादमी के मार्ग निर्देशन में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में नीतिगत सलाह, रणनीतिक योजना, प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास गतिविधियों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सी0जी0जी0 राज्य एवं केन्द्रीय नवीन अनुसंधानों, पहलों के लिए के0ए0पी0 (ज्ञान दृष्टिकोण एवं अभ्यास) अध्ययन एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का भी कार्य करता है।

वर्ष 2019–20 में नियमित संकाय सदस्यों की अल्प संख्या के बावजूद अकादमी, डी0एम0सी0 एवं सी0जी0जी0 के अन्तर्गत कुल 129 प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उत्तराखण्ड एवं देश के कुल 4,156 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों सहित राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं। डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। आन्तरिक स्तर पर विभागीय मैन्युअल, कर्मचारियों के दायित्व का विवरण विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया है।

यह हर्ष का विषय है कि अकादमी के समस्त कार्यों का संचालन विकेन्द्रित रूप में विभिन्न टीमों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। निःसंदेह इससे कार्मिकों में एक नये उत्साह का संचार, स्वाभिमान व टीम भावना का विकास एवं संस्था के प्रति प्रगाढ़ अपनत्व का भाव भी जागृत हुआ है। इसका अनुभव प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों द्वारा उनके अकादमी प्रवास में भी किया गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि यह टीम भावना अकादमी को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।

अन्त में, मैं अकादमी के समस्त संकाय सदस्यों, प्रशिक्षण समन्वय इकाई (टी0सी0यू0) की टीम तथा अन्य विभिन्न इकाईयों की टीमों की विशेष रूप से सराहना करना चाहूँगा जिनके प्रयासों से वर्ष 2019–20 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफल आयोजन एवं तत्सम्बन्धित व्यवस्थाओं का सफल सम्पादन हो सका। प्रशिक्षण समन्वय इकाई के सतत प्रयासों से ही यह वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20 प्रकाशित होना सम्भव हो सका है। इसके लिए मैं अकादमी के समस्त संकाय सदस्यों एवं कार्मिकों को साधुवाद करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि, वर्ष 2020–21 में भी ***'डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल'*** राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर अपनी उत्कृष्टता को मानकों के अनुसार स्थापित करने में सक्षम हो सकेगी तथा अकादमी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की प्राथमिकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार प्रशिक्षण को राज्य में एक नवीन दिशा एवं प्राथमिकता प्रदान करने में विशेष योगदान सतत रूप से दिया जाता रहेगा।

'हार्दिक शुभकामनाओं सहित''

राजीव रौतेला
निदेशक

अनुक्रमणिका

1. डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

I. अकादमी : एक परिचय

II. अकादमी की विभिन्न संगठनात्मक इकाईयाँ/अनुभाग
(1) पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र
(2) कम्प्यूटर अनुभाग
(3) दृश्य–श्रृव्य अनुभाग
(4) प्रशिक्षण समन्वय इकाई
(5) सूचना का अधिकार केन्द्र

III. अकादमी की अवस्थापना सुविधाएँ
(1) अकादमी ऑफिसर्स मैस, अतिथि गृह तथा छात्रावास
(2) प्रशिक्षण कक्ष तथा प्रेक्षागृह
(3) क्रीड़ा एवं खेलकूद

IV. अकादमी की प्रशिक्षण गतिविधियाँ तथा अन्य विवरण

2. आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ

3. सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स

(1) प्रोजक्ट प्लानिंग एण्ड परफॉरमेन्स बजटिंग इकाई
(2) ई–गवर्नेन्स इकाई
(3) प्रलेखन एवं समन्वय इकाई
(4) नगरीय कार्य इकाई
(5) की–रिसोर्स सेन्टर, पेयजल एवं स्वच्छता इकाई
(6) बौद्धिक संपदा एवं मानवाधिकार इकाई
(7) जेन्डर इश्यूज इकाई

4.प्रशिक्षण गतिविधियों का चार्ट निरूपण

5.प्रशिक्षण गतिविधियों की कुछ झलकियाँ

6. वर्ष 2019–2020 में अकादमी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची

7. वर्ष 2019–2020 में सी.जी.जी. द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची

8. अकादमी के वर्तमान निदेशक एवं संकाय

I. अकादमी : एक परिचय

डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी परिसर का बहुत रोचक एवं गौरवपूर्ण इतिहास है। सन् 1951 में ''अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल'' के नाम से इलाहाबाद में स्थापित इस संस्थान को जब सन् 1971 में नैनीताल के शान्त एवं सुरम्य वातावरण में लाने का निर्णय लिया गया तब आर्डवैल (उच्चस्थ नगर –High Town) कैम्प परिसर को इस संस्थान की स्थापना के लिए चुना गया। आर्डवैल कैम्प में निर्मित बैरेक्स द्वितीय विश्वयुद्ध के समय रॉयल एयरफोर्स के अधिकारियों के अस्थायी आवास के लिए आर्डवैल बैरेक्स के रूप में निर्मित किए गए थे। ब्रिटिश अधिकारियों, सिपाहियों के अतिरिक्त इन बैरेक्स में अमेरिकन अधिकारी भी रहते थे। आर्डवैल कोठी जो कि आज निदेशक आवास है स्वतंत्रता से पूर्व कुमाऊँ कमिश्नर का आवास हुआ करती थी। एवर्सले हाउस, जो अतिथि गृह एवं मुख्य सचिव आवास है. को पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त द्वारा 1957 में ले लिया गया था तब उसमें श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, वित्त मंत्री, संयुक्त प्रान्त रहते थे। बाद में इसे शासकीय कार्यों के लिए ले लिया गया। आर्डवैल प्रांगण में बैरेक्स और क्वार्टरों के साथ एक हॉल का निर्माण किया गया था (वर्तमान बैटमिंटन एवं टी.टी. हॉल) जो अंग्रेज फौजियों को अंग्रेजी चलचित्र दिखाने के लिये काम में आता था, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर डोरमेटरी के रूप में भी इसका प्रयोग होता था। दिनाँक 15 मई, 1947 से दिनाँक 6 जून, 1947 तक संयुक्त प्रान्त लेजिसलेटिव असेम्बली की 16 बैठकें आर्डवैल हॉल में आयोजित हुई थी। डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी परिसर में स्थित आर्डवैल हॉल में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व आयोजित संयुक्त प्रान्त लेजिससेटिव असेम्बली की बैठकों के पदाधिकारी के रूप में अध्यक्ष माननीय श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन, उपाध्यक्ष श्री नफीसुल हसन, सचिव श्री कैलाश चन्द्र भटनागर इत्यादि कई अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया था।

उत्तराखण्ड में, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल को एक शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तद्नुसार अकादमी, शासन तंत्र एवं अकादमी के उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन प्रतिवर्ष सफलतापूर्वक करती आ रही है। अकादमी की स्थापना वर्ष 1951 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश संवर्ग) तथा राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इलाहाबाद में 'अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल (ओ.टी.एस.)' के रूप में की गयी। वर्ष 1958 में इस स्कूल में प्रादेशिक न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण आरम्भ किया गया। वर्ष 1961 तक स्कूल में प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण वर्ष 1961 में स्कूल की गतिविधियाँ तात्कालिक रूप से स्थगित कर दी गयीं।

वर्ष 1971 में पुनः अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल को नैनीताल के वर्तमान परिसर में स्थापित कर दिया गया. नैनीताल में आयुक्त स्तर के अधिकारी को इस स्कूल का पूर्णकालिक प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। वर्ष 1974 में स्कूल के नाम को परिवर्तित कर 'प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान कर दिया गया। वर्ष 1976 से संस्थान के विभिन्न पदों के पदनाम भी बदल दिये गये। संस्थान में अब महानिदेशक/निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा

सहायक निदेशक नियुक्त किये गये। प्रशिक्षण के बदलते स्वरूप एवं संस्थान की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए वर्ष 1988 में इसे प्रदेश का शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान घोषित किया गया तथा संस्थान की बढ़ती गतिविधियों एवं बदलते लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इसका नाम परिवर्तित करते हुए इसे 'उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी' कर दिया गया। उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी इस अकादमी का मुखिया होते हैं।

9 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड के रूप में नए राज्य का गठन हुआ। राज्य गठन के पश्चात यह 'उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी' के रूप में स्थापित है एवं उत्तराखण्ड राज्य की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था के रूप में अपने दायित्वों को पूर्ण कर रही है। वर्तमान में अकादमी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है अकादमी वर्तमान में सम्मिलित राज्य सेवा के अधिकारियों हेतु आधारभूत/सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कोर्सों के अतिरिक्त प्रादेशिक सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा), भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग), भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के अधिकारियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रही है। इनके अतिरिक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.), भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) तथा भारत सरकार व प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए सेवाकालीन तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सभी अधिकारियों के लिए एक माह का सेवा प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। सेवा प्रवेश प्रशिक्षण का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य की चुनौतियों तथा अवसरों के बारे में नव–नियुक्त अधिकारियों को अद्यतन सूचना से अवगत कराना तथा उनमें प्रबन्धकीय कौशल का विकास करना है, जिससे वे अपने–अपने क्षेत्रों में गुणात्मक सेवाएँ प्रदान कर सकें, तथा उनमें उत्तराखण्ड राज्य की सामाजिक–आर्थिक, साँस्कृतिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में उचित समझ विकसित हो सके। अकादमी द्वारा राज्य के अधिकारियों के क्षमता विकास हेतु अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे वह सुयोग्य, व्यावसायिक एवं प्रतिबद्धतापूर्ण लोक सेवक के रूप में राज्य के विकास में सहयोग दे सकें। अकादमी द्वारा कई ऐसे विभागों के लिए भी क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिनके पास संस्थागत प्रशिक्षण आयोजित करने की सुविधाएँ नहीं हैं या प्रशिक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण सीमित संसाधनों से प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।

अकादमी द्वारा प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य के अधिकारियों हेतु विभिन्न सामयिक विषयों एवं क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नयी सदी में प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत अकादमी द्वारा प्रशिक्षक कौशल विकसित करने में सहायक कार्यक्रम जैसे Direct Trainer Skills, Design of Training, Evaluation of Training एवं Training Techniques इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। अकादमी को ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश सरकार तथा प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के सौजन्य से भारत में चलाई जा रही 'प्रशिक्षक विकास योजना' के अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में ही देश के पाँच प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में से एक प्रमुख केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। इसके अन्तर्गत अकादमी देश व प्रदेश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत् प्रशिक्षण संकाय को प्रत्यक्ष प्रशिक्षण की कला, प्रशिक्षण डिजाइन, प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण, प्रशिक्षण प्रबन्धन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करती है।

डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। आन्तरिक स्तर पर विभागीय मैनुअल, कर्मचारियों के दायित्व का विवरण विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया है। साथ ही उप–निदेशक को लोक सूचना अधिकारी तथा संयुक्त निदेशक को अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। अकादमी में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक अलग प्रकोष्ठ उप निदेशक के अधीन गठित किया गया है। प्रशासन में सुधार हेतु 'सूचना तक पहुँच' को एक मुख्य क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। 'सूचना तक पहुँच' को एक मुख्य विकासात्मक मुद्दे के रूप में मान्यता दी गयी है, क्योंकि यह प्रशासन को अधिक

पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन

डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल देश के एक शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान के रूप में अपने को स्थापित करने में निरन्तर प्रयासरत् रही है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि एक सुव्यवस्थित कार्य प्रक्रिया को अकादमी द्वारा न केवल अपनाया जाता रहा है बल्कि इसके विकास हेतु अभिनव प्रयासों एवं नवीन पहलों को भी प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। इस क्रम में पूर्व में किए गये अभिनव प्रयासों एवं नवीन पहलों को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से अकादमी द्वारा पूर्णगुणवत्ता प्रबन्धन के क्षेत्र में विशेष प्रयास किए गये हैं।

अकादमी द्वारा निरन्तर यह प्रयास रहा है कि प्रशिक्षण के क्षेत्र में और बेहतर कार्य किया जाये, जिससे कि अकादमी को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को मूर्त रूप दिया जा सके। इसके लिए निम्नांकित व्यवस्थाएँ की गई हैं:–

- विकेन्द्रीकृत प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए अकादमी के आन्तरिक प्रशासन में अधिकार एवं दायित्व का विकेन्द्रीकरण।
- लागत प्रभावकारिता–प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और उद्देश्य के दृष्टिकोंण को ध्यान में रखते हुए आय और व्यय पर नियंत्रण।
- प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कार्ययोजना के निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में समस्त कार्मिकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।
- कार्ययोजना को मूर्त रूप देने एवं सफल बनाने हेतु प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा एवं सुधार हेतु सतत् प्रयास करना।
- राज्य प्रशिक्षण नीति के क्रियान्वयन तथा प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के अग्रणी संस्थान के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन।
- प्रशासन में नवीन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षणार्थियों में आवश्यक कौशल एवं रचनात्मक विचारों का विकास।

उत्तरदायी तथा सहभागी बनाने के साथ शक्ति के निरंकुश प्रयोग पर रोक लगाकर अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। सूचना का अधिकार जनता को उनके अधिकारों की अनुभूति कराता है और विकासात्मक मुद्दों पर जनसहभागिता बढ़ाने की अद्भुत सामर्थ्य प्रदान करता है। अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा यू. एन.डी.पी. के सहयोग से सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।

आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ का गठन कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल में राज्य स्तर की इकाई के रूप में वर्ष 1995 में किया गया था। 09 नवम्बर, 2000 को उत्तराखण्ड के रूप में नए राज्य का गठन हुआ। राज्य के अधिकतर क्षेत्र भूकम्पीय जोन में होने के कारण शासन स्तर से आपदा प्रबन्ध एवं न्यूनीकरण केन्द्र की स्थापना की गई थी इसलिए यह केन्द्र भी देहरादून में आपदा प्रबन्ध एवं न्यूनीकरण केन्द्र में ही सम्मिलित कर लिया गया था। परन्तु उद्देश्यों में अन्तर होने की वजह से जुलाई 2006 में आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ पुनः उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में स्थापित किया गया। आपदा प्रबन्ध प्रकोष्ठ का कार्य मुख्यतः दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में सूचनाओं का संकलन, डॉक्युमेन्टेशन, आपदा प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक्शन प्लान का निर्धारण, पूर्व तैयारी, जागरुकता तथा प्रशिक्षण, कन्सलटेन्सी, शोध तथा क्षमता विकास इत्यादि के कार्य संचालित होते हैं।

अकादमी का मुख्य परिसर आर्डवैल कैम्प, मल्लीताल, नैनीताल में स्थित है। संगठनात्मक अध्यक्ष के रूप में अकादमी में सचिव स्तर के आई.ए.एस. अधिकारी, निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिन्हें विभागाध्यक्ष के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। आलोच्य वर्ष में अकादमी में विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ अकादमी संकाय सदस्यों के रूप में राज्य सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, संयुक्त निदेशक के रूप में, राज्य सिविल सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के रूप में व पांच उप–निदेशक कार्यरत रहे। अकादमी में कार्यरत संकाय सदस्यों को अपने–अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता एवं पर्याप्त अनुभव प्राप्त है।

II. अकादमी की विभिन्न संगठनात्मक इकाईयाँ/अनुभाग

(1) पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र

पुस्तकालयों के माध्यम से मानव अपने दृष्टिकोणों, विचारों एवं अनुभवों तथा स्वपनों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सम्प्रेषित करता है। भविष्य का निर्माण करने में पुस्तकालय सोपान भी हैं और अतीत की कड़ी भी, पुस्तकालय वर्तमान से भविष्य की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। पुस्तकालय जैसी संस्था वर्तमान प्रजातंत्रीय युग की एक अभूतपूर्व देन है। किसी भी संस्था के सर्वांगीण विकास का आधार साक्षरता तथा शिक्षा का प्रसार है, किसी भी देश अथवा प्रदेश की सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक और आर्थिक स्तर ऊँचा करने में पुस्तकालयों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र किसी भी संस्था की महत्वपूर्ण इकाई होती है। पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र में न केवल प्रशिक्षण, शोध तथा विभिन्न विषयों से संबंधित प्रलेखों का संकलन किया जाता है, बल्कि पूरे संस्थान में होने वाली समस्त अकादमिक गतिविधियों का लेखा–जोखा भी प्रलेखन कार्य के रूप में करते हुए सुरक्षित रखा जाता है।

अकादमी द्वारा पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र के विकास के लिए काफी प्रयास किये जा रहे हैं। अकादमी पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र न केवल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अधिकारियों को सुविधा प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय में शोध कर रहे छात्रों को भी आवश्यक सूचना एवं परामर्श प्रदान करता है। अकादमी पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र पूर्णतयाः कम्प्यूटरीकृत है, आगम–निर्गम, संदर्भ सेवा, प्रलेखन सेवा इत्यादि में कम्प्यूटर का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है।

अकादमी पुस्तकालय को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैक के अलावा आई.एम.एफ., आई.एल.ओ. तथा यूनाइटेड नेशन्स, आई.सी.मोड के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं से उनके प्रकाशन निःशुल्क प्राप्त होते हैं। अकादमी पुस्तकालय का उपयोग प्रतिवर्ष लगभग 5,000 से 6,000 के मध्य प्रशिक्षार्थी अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों, तथा विशिष्ट पाठकों द्वारा किया जाता है, इसमें प्रदेश के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारी, संकाय अधिकारी, प्रशिक्षार्थी अधिकारी, कर्मचारियों और स्थानीय विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ता तथा जिले में तैनात वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अकादमी का पुस्तकालय पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत है। कम्प्यूटरीकरण हेतु लिबसिस साफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। पुस्तकालय अपने पाठकों को अन्य सुविधाओं के अलावा इन्टरनेट की सुविधा भी प्रदान करता है।

- ## पुस्तकालय कार्य समय

पुस्तकालय प्रातः 08:00 से सायंकाल 8:00 बजे तथा राजपत्रित अवकाशों में आवश्यकतानुसार प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक खुला रहता है।

पुस्तकालय संग्रह

- पुस्तकें और रिपोर्ट्स
- सामायिक प्रकाशन / वार्षिक प्रतिवेदन
- वीडियों कैसेटस एवं सीडी रोम्स
- राष्ट्रीय समाचार पत्र एंव पत्रिकायें
- उत्तराखण्ड व राष्ट्रीय / प्रादेशिक मानचित्र
- कम्प्यूटर आधारित सामग्री व ई–बुक्स
- विश्व बैंक व अन्य संस्थाओं के डिजिटल प्रलेख

विशेष संग्रह

- विश्व बैंक प्रकाशन
- विश्वकोष
- संदर्भ ग्रंथ
- जनगणना पुस्तिकाएँ
- गजेटियर
- हिमालयन गजेटियर
- एआईआर मैनुअल
- विभागीय मैनुअल
- लॉ ऑफ अमेरिका
- लॉ ऑफ इग्लैण्ड
- बाउण्ड पत्रिकाएँ
- रिर्पोर्ट्स व वार्षिक रिर्पोर्ट्स
- वीडियों कैसेट्स एवं सीडी साफ्ट्वेयर
- सेटिलमेन्ट रिपोर्ट्स
- हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैण्ड

दिनाँक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष में अकादमी पुस्तकालय में विश्व बैंक, यूनिसेफ व अन्य संस्थाओं से प्राप्त प्रलेखों तथा जिल्दबन्द पत्रिकाओं को शामिल करते हुये कुल 98,926 प्रलेख अभिलेखों में दर्ज हैं तथा वार्षिक वृद्धि 1,068 प्रलेखों की हुई है। सामान्य प्रलेखों के अलावा विभिन्न स्रोतों से लगभग 2,300 सी.डी. जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल प्रलेख भी शामिल हैं, का भी संकलन हुआ है। अकादमी द्वारा लगभग 25 से अधिक भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाएँ अभिदत्त की गई हैं। कुछ पत्रिकाओं के डिजिटल संस्करण भी अभिदत्त की गई हैं। पुस्तकालय में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों पर पाठकों को इन्टरनेट सेवा प्रदान की जा रही है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष में परिग्रहण पंजिकाओं में दर्ज प्रलेखों की संख्या इस प्रकार है :–

1.	परिग्रहण पंजिका अंग्रेजी	EG	40,995
2.	परिग्रहण पंजिका हिन्दी	H	14225
3.	परिग्रहण पंजिका लॉ	EL	16,085
4.	विभागीय प्रकाशन	DP	4,491
5.	जिल्द बन्द लॉ जर्नल्स	BLJ	2,500

6.	जिल्द बन्द पत्रिकाएं	BP	2,505
7.	विश्व बैंक प्रकाशन	WB	8,182
8.	परिग्रहण पंजिका सी.डी.एस.	CD	635
9.	श्री बलराज पासी संकलन		158
10.	सी.डी. रिपोर्टस		1,250
11.	सी.डी. रोम्स		2,300
12.	अन्य प्रलेख		5,000
13.	फोटो एलबम		600
	कुल योग		**98926**

• विश्व बैंक डिपाजिटरी लाइब्रेरी

अकादमी पुस्तकालय वर्ष 1986–2012 तक विश्वबैंक की डिपॉजिटरी लाईब्रेरी परियोजना का सदस्य रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक के महत्वपूर्ण प्रलेख अकादमी को सीधे प्राप्त होते रहे हैं। तत्समय में इस परियोजना के अन्तर्गत अकादमी में प्रदेश का एकमात्र पुस्तकालय था, जिसको डिपॉजिटरी लाईब्रेरी का दर्जा प्राप्त था। इस परियोजना के अन्तर्गत अकादमी पुस्तकालय को वर्ल्ड बैंक की ई–लाईब्रेरी इस्तेमाल करने का लाईसेंस प्रदान किया गया है। इसका इस्तेमाल संकाय अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय उच्च अधिकारी, शोध–छात्र, शिक्षक, तथा अन्य जिज्ञासु व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। अकादमी पुस्तकालय द्वारा यह सेवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। अकादमी में स्थापित वर्ल्ड बैंक डिपॉजिटरी लाईब्रेरी उत्तराखण्ड राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्ति का केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। विश्व बैंक ई–लाईब्रेरी के रूप में अकादमी पुस्तकालय को एक महत्वपूर्ण डिजिटल डाटाबेस उपलब्ध है जिनका इस्तेमाल अकादमी पुस्तकालय एवं अकादमी सर्वर से जुड़े किसी भी नोड से किया जा सकता है।

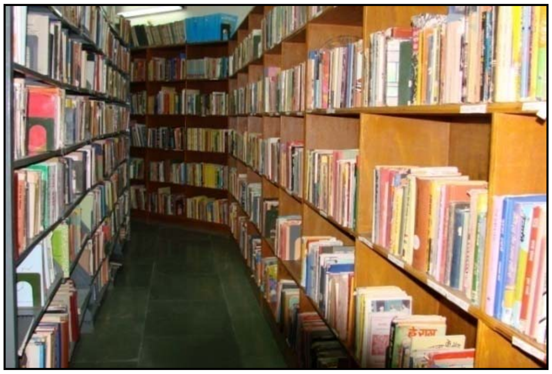

सेवाएँ

पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण सेवाएँ निम्नवत् हैं :–

नवागत प्रलेखों का परिचालन	सन्दर्भ सेवा	सामयिक विवरणिका	पुस्तक आदान–प्रदान सेवा
प्रतिलिपीकरण सेवा	प्रलेखन सेवा	कम्प्यूटर आधारित सेवाएँ	इन्टरनेट सुविधा

- **कम्प्यूटरीकरण :**

अकादमी पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु लिबसिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया जा चुका है। अंग्रेजी विषयक सभी पुस्तकों का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है। अभी पुस्तकालय कम्प्यूटरीकरण के लिए लिबसिस सॉफ्टवेयर का संस्करण प्रयोग किया जा रहा है। पुस्तकों की खोज में पाठकों को आसानी हो इसके लिए पुस्तकालय द्वारा प्रत्येक पुस्तक का बारकोड भी तैयार कर पुस्तक पर लगाया जा रहा है।

- **सदस्यता :**

अकादमी पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र की सदस्यता अकादमी में कार्यरत समस्त संकाय अधिकारी तथा प्रशिक्षणार्थी अधिकारी तथा कर्मचारी सदस्यता का पंजीकरण करवा सकते हैं, इनके अलावा वरिष्ठ अधिकारीगण, शोध छात्र, स्थानीय विश्वविद्यालय के अध्यापकगण भी विशेष उपबन्ध के अन्तर्गत सदस्यता का पंजीकरण करवा सकते हैं। वर्ष 2019–20 में पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र द्वारा लगभग 5000 विशिष्ट पाठकों/सदस्यों को पुस्तकालय की सेवाएं प्रदान की गई।

❖ संकाय (अकादमी एंव सी.जी.जी.)	13
❖ प्रशिक्षार्थी अधिकारी	3,500
❖ कर्मचारी (अकादमी एंव जी.जी.)	100
❖ शोध एवं अन्य छात्र	200

- **प्रलेखों का व्यवस्थापन :**

वर्गीकरण एवं सूचीकरण कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है। वर्गीकरण के लिए Dewey Decimal Classification DDC-22 and 23rd Edition एवं सूचीकरण के लिए AACR-II का प्रयोग किया जा रहा है। अकादमी पुस्तकालय लैन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दिनाँक 31 मार्च, 2020 तक प्राप्त सभी प्रलेखों को वर्गीकृत कर कम्प्यूटर में दर्ज कर दिया गया है। वर्गीकरण एवं सूचीकरण कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है।

(2) कम्प्यूटर अनुभाग

डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में लगभग सभी अनुभागों में कम्प्यूटर का प्रयोग दिन–प्रतिदिन के कार्यों में किया जा रहा है। स्वागत कक्ष, लेखाकक्ष, अधिष्ठान, मैस, पुस्तकालय एवं प्रशिक्षण, सभी अनुभागों में कम्प्यूटर की व्यवस्था एवं देखभाल इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। कम्प्यूटर हार्डवेयर

तथा सॉफ्टवेयर की मरम्मत एवं अनुरक्षण इस अनुभाग की देख–रेख में किया जाता है। वर्तमान में अकादमी परिसर के प्रत्येक कक्ष में कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं। इस समय में अकादमी के विभिन्न कक्षों में लगभग 112 आधुनिक कम्प्यूटर स्थापित हैं, साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए चौखम्बा भवन के द्वितीय तल पर आधुनिकतम सुविधायुक्त कम्प्यूटर लैब व्यवस्थित है। कम्प्यूटर लैब में 20 कम्प्यूटर्स स्थापित किये गये हैं। ये सभी कम्प्यूटर्स लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं, साथ ही सभी कम्प्यूटर्स इन्टरनेट सुविधा से युक्त हैं। अकादमी के अतिथि गृह तथा छात्रावासों में इन्टरनेट सुविधा से युक्त कम्प्यूटर्स प्रशिक्षार्थी अधिकारियों को उपलब्ध करवाये गए हैं। कम्प्यूटरीकरण की दिशा में अकादमी पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, मैस तथा लेखा अनुभाग के कम्प्यूटरीकरण की दिशा में काफी प्रगति हुई है। अकादमी के स्वागत कक्ष के लिए ऑनलाईन रूम रिजर्वेशन तथा ऑनलाईन बिलिंग से संबंधित सॉफ्टवेयर का निर्माण कर स्वागत–कक्ष को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप कार्यक्रमवार छात्रावासों तथा अतिथिगृहों में कक्षों का आरक्षण तथा उसी के आधार पर मैस बिलों का भुगतान इत्यादि भी कम्प्यूटर के माध्यम से किया जाता है। इन सभी अनुभागों में कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की देखरेख का कार्य अकादमी, कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। कम्प्यूटर अनुभाग द्वारा राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अकादमी में आयोजित किये जाने वाले आधारभूत/व्यावसायिक/सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। अकादमी परिसर को पूर्णरूप से वाई–फाई से सज्जित कर दिया गया है, साथ ही अकादमी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अकादमी परिसर को पूर्णरूप से सी.सी.टी.वी. कैमरे से सज्जित कर दिया गया है।

(3) दृश्य–श्रृव्य अनुभाग

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए चर्चा कक्षों में उपयुक्त वातावरण तैयार करने तथा दृश्य–श्रव्य उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए अकादमी में दृश्य–श्रव्य अनुभाग की स्थापना की गई है। इस अनुभाग में नवीन दृश्य–श्रव्य उपकरण तथा चर्चा कक्षों की गतिविधियों का चित्रांकन, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, ओवर हेड प्रोजक्टर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम इत्यादि नवीनतम उपकरणों की व्यवस्था इस अनुभाग द्वारा की जाती है। इस अनुभाग के माध्यम से अकादमी में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों का चित्रांकन/रिकार्डिंग आदि कर एल्बम एवं सी0डी0 के रूप में सन्दर्भ हेतु संकलित किया जाता है।

(4) प्रशिक्षण समन्वय इकाई

प्रशिक्षण एवं सम्बन्धित कार्य को अकादमी में व्यवस्थित रूप से करने के उद्देश्य से सभी डिवीजनों की गतिविधियों में समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य **'प्रशिक्षण समन्वय इकाई (टी.सी.यू.)'** के द्वारा किया जाता है। अकादमी द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों एवं इनमें प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए एवं आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के सफल आयोजन के उद्देश्य से वर्ष 1999 में अकादमी द्वारा 'प्रशिक्षण समन्वय इकाई (टी.सी.यू.) का गठन किया गया। प्रशिक्षण समन्वय का मुख्य उद्देश्य अकादमी के विभिन्न डिवीजनों द्वारा गठित कार्यात्मक टीमों एवं सी.जी.जी. के विभिन्न प्रोजेक्ट मनैजमेन्ट यूनिटस के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना है, जिससे कि आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों को सफल बनाया जा सके। प्रशिक्षण समन्वय यूनिट द्वारा प्रशिक्षार्थी अधिकारियों की सुविधा हेतु प्रत्येक गतिविधि आयोजन के एक माह पूर्व योजना निर्धारित की जाती है। इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु एक सूचना–पत्र जिसे **'विन्डो कैलेण्डर'** कहा जाता है, को प्रस्तावित गतिविधि सप्ताह के पूर्व सप्ताह में निर्गत किया जाता है, जिससे कि समस्त टीम लीडर जिसमें मैस, स्वागत कक्ष, हॉस्टल इत्यादि सम्मिलित हैं, इस सूचना के माध्यम से समस्त टीम लीडरों से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा सम्बन्धित गतिविधियों के आयोजन से सम्बन्धित समस्त तैयारियों को समय से पूर्ण कर लें। **'वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर'** एवं **'वार्षिक प्रतिवेदन'** का लेखन, डिजाइन एवं प्रकाशन के अतिरिक्त प्रतिभागियों की आवासीय व्यवस्था, चर्चा कक्षों की व्यवस्था तथा उससे जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं का समन्वय एवं आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित कार्यक्रम निदेशकों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य भी टी0सी0यू0 द्वारा किया जाता है, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। इसके अन्तर्गत चर्चा कक्षों का आवंटन, छात्रावास की स्थिति, तथा कार्यक्रमों के मध्य में सभी सम्बद्ध पक्षों से वार्ता कर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। अकादमी की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में प्रतिभागी अधिकारियों का फीड–बैक काफी सराहनीय रहा।

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम

डा0 आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। आन्तरिक स्तर पर विभागीय मैनुअल, कर्मचारियों के दायित्व का विवरण विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया है, साथ ही अकादमी के संयुक्त निदेशक को लोक सूचना अधिकारी तथा अपर निदेशक को अपीलीय अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। अकादमी में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एक अलग प्रकोष्ठ उप–निदेशक के अधीन गठित किया गया है। प्रशासन में सुधार हेतु 'सूचना तक पहुँच' को एक मुख्य क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। 'सूचना तक पहुँच' को एक मुख्य विकासात्मक मुद्दे के रूप में मान्यता दी गयी है, क्योंकि यह प्रशासन को अधिक उत्तरदायी तथा सहभागी बनाने के साथ शक्ति के निरंकुश प्रयोग पर रोक लगाकर अधिक पारदर्शिता को

सुनिश्चित करता है। जैसे कि यह जनता को उनके अधिकारों की अनुभूति कराता है और विकासात्मक मुद्दों पर जनसहभागिता बढ़ाने की अद्भुत सामर्थ्य रखता है।

(III) अकादमी की अवस्थापना सुविधाएँ

(1) अकादमी आफिसर्स मैस, अतिथि गृह तथा छात्रावास

अकादमी में विभिन्न उत्कृष्ट उपकरणों से सुसज्जित मैस है। इसमें एक समय में 150 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। मैस में भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। यह

सम्पूर्ण व्यवस्था मैस प्रबन्धक की देख–रेख में की जाती है। व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन हेतु मैस विंग बनाया गया है। मैस के उचित संचालन के लिए अकादमी संकाय सदस्यों में से एक सदस्य को प्रभारी अधिकारी, मैस का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जिनके अधीन मैस प्रबन्धन हेतु एक मैस इन्चार्ज भी नियुक्त किया गया है। मैस विंग के द्वारा भी सभी अन्य विंगों की भाँति नियत समय पर बैठकें की जाती हैं, और भोजन की गुणवत्ता, आय–व्यय इत्यादि से सम्बन्धित निर्णय लिये जाते हैं, इन्ही निर्णयों के अनुसार विंग द्वारा समस्त कार्यों का सम्पादन किया जाता है। मैस के सामने ही अकादमी का लाउन्ज स्थित है, इसका उपयोग महत्वपूर्ण समारोहों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विशिष्ट अतिथियों के आगमन, स्वागत व विशेष भोज के अवसरों पर किया जाता है। सामान्य दिवसों में यह टेलीविजन के कार्यक्रमों को देखने के लिये निर्धारित समय पर खुला रहता है। बदलते हुए परिदृश्य एवं माँग

के अनुरूप अकादमी की सेवाओं एवं सुविधाओं में गुणवत्ता बनाये रखना तथा इनका रख–रखाव एक बड़ी चुनौती है। अकादमी मैस ने प्रारम्भ के वर्षो में इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया है तथा खान–पान सेवाओं के क्षेत्र में हुई प्रगति, मशीनीकरण व तकनीकी विकास और लोगों के खान–पान की आदत में आए परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में स्वंय को ढालने का निरन्तर प्रयत्न किया है। प्रशिक्षार्थी अधिकारियों के लिए आवासीय व्यवस्था हेतु अकादमी में क्रमशः ''यमुनोत्री'' और ''गंगोत्री'' नामक दो छात्रावास हैं। इनमें लगभग 150 अधिकारियों के ठहरने की उच्च कोटि की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अकादमी ''अलकनंदा'' तथा ''भिलंगना'' अतिथि गृहों में विशिष्ट अतिथियों हेतु आधुनिक सुख–सुविधाओं युक्त क्रमशः 09 तथा 06 कक्ष सुव्यवस्थित है, जिनमें उत्तराखण्ड शासन के उच्चाधिकारियों तथा विशिष्ट अतिथि प्रवक्ताओं के लिए आवासीय व्यवस्था की जाती है।

(2) प्रशिक्षण कक्ष तथा प्रेक्षागृह

अकादमी के त्रिशूल भवन तथा चौखम्बा भवन में कुल 10 चर्चा–कक्ष विद्यमान हैं। सभी चर्चा–कक्षों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। अकादमी के त्रिशूल भवन में ही आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रेक्षागृह है जिसमें एक समय में 200 व्यक्तियों के बैठने की आरामदायक व्यवस्था है। इस प्रेक्षागृह का उपयोग प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों के अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये किया जाता है। विशिष्ट अवसरों पर इसी प्रेक्षागृह में क्षेत्र व प्रदेश के सांस्कृतिक दलों द्वारा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं।

(3) क्रीड़ा एवं खेल–कूद सुविधाएँ

अकादमी परिसर में स्थित 'भागीरथी' जो एक ऐतिहासिक भवन है, में स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स स्थापित है। इसमें बिलियर्ड, बैडमिन्टन, टेबल टैनिस, भारोत्तोलन, व्यायाम, शतरंज, कैरम इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। आउटडोर गतिविधियों में लॉन टैनिस तथा वालीबाल की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं में सहायता करने के लिये पी.टी.आई. एवं क्रीड़ा सहायक भी अकादमी में नियुक्त हैं। वर्ष 1999 में, प्रशिक्षार्थियों की माँग पर एक आधुनिक व्यायामशाला (ज़िम) की स्थापना भी की गई है। संदर्भित वर्ष के दौरान दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों द्वारा सत्रान्त तक निरन्तर खेल–कूद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी दीर्घकालीन प्रशिक्षणों के प्रतिभागियों की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और विजेता प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के समापन समारोह में पुरस्कृत किया गया। अकादमी में खेल–कूद व योगा इत्यादि की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इन्डोर व आउटडोर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न अवस्थापनाओं का विकास निरंतर किया जा रहा है। क्रिकेट, वॉलीबाल तथा लॉन–टैनिस के लिए उच्च कोटी के फील्ड्स तैयार कराये जा रहे है। आगामी वर्षो में इसका लाभ प्रशिक्षु अधिकारियों को उपलब्ध हो जायेगा।

(IV) अकादमी की प्रशिक्षण गतिविधियाँ तथा अन्य विवरण

प्रदेश के समग्र विकास के लिये, विभिन्न विभागों/संगठनों, लोकतांत्रिक निकायों, जन प्रतिनिधियों, सरकारी तथा गैर–सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रदेश के विकास में इन संस्थानों की कुशलता और प्रभाविकता इनमें कार्यरत कार्मिकों की कार्यकुशलता एवं योग्यता पर निर्भर करती है। संदर्भित वर्ष में अकादमी व परियोजना आधारित प्रशिक्षणों को संचालित करने के उद्देश्य से अकादमी में स्थापित सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सम्बन्धित गतिविधियों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी पृथक रूप से दी गई हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य

- ❖ कार्मिकों में बेहतर कार्य निष्पादन हेतु व्यावहारिक ज्ञान एवं क्षमता विकास।
- ❖ बदलती सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों में संवेदनशील और उत्तरदायित्वपूर्ण क्षमता का विकास।
- ❖ गैर सरकारी/स्वयंसेवी संस्थानों व निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों की क्षमता का विकास।
- ❖ प्रशिक्षण आयोजना एवं संरचना का विकास ताकि समूह क, ख के सभी लोकसेवकों को प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त हो सकें।
- ❖ सामयिक विषयों पर कार्यशालाओं, संगोष्ठी और सम्मेलनों के आयोजन से विचारों का आदान–प्रदान, विचार–विश्लेषण एवं संवाद।

अकादमी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमः

- **व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

अखिल भारतीय सेवा के प्रशिक्षार्थी अधिकारियों हेतु आयोजित किये जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य प्रशिक्षार्थी अधिकारियों को सम्बन्धित कार्यक्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी क्षमता एवं आत्मविश्वास में वृद्धि करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों में प्रशिक्षार्थियों में निर्णय क्षमता के विश्लेषणात्मक पक्षों का विकास, विकास कार्यक्रमों की समस्याओं के समाधान में कौशल एवं क्षमतापूर्वक दायित्व निर्वहन एवं नवसृजित राज्य उत्तराखण्ड की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से उन्हें अवगत करना सम्मिलित है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत, सिविल एवं राजस्व विधि, नियोजन एवं विकास, कृषि संरचना एवं ग्राम्य विकास तथा विधिक निर्णय लेखन आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। मुख्य रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की कार्यक्षमता व कौशल में वृद्धि के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों हेतु अकादमी द्वारा पाँच सप्ताह तथा अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों हेतु 12–सप्ताह तथा प्रादेशिक सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के

अधिकारियों हेतु 10–सप्ताह के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन किये जाने का प्रावधान है। आलोच्य वर्ष 2019–2020 में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों हेतु **17वाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किया गया, इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 06 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों हेतु अकादमी में 10वाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय वन सेवा के 02 परिवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- ## आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम

आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य प्रशिक्षार्थी अधिकारियों को प्रदेश तथा सम्बन्धित कार्यक्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना होता है। चूँकि आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नवागत अधिकारियों के लिए किया जाता है, इसलिए इस कार्यक्रम में ऐसे कार्यक्रमों का समायोजन किया जाता है जो एक व्यक्ति को देश एवं प्रदेश के आवश्यकतानुसार कार्य करने के लिए तैयार कर सकें। आलोच्य वर्ष में अकादमी द्वारा राज्य सिविल सेवा के प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों हेतु 14वाँ आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसमें राज्य सिविल सेवा के 48 अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

- ## लक्ष्य एवं उद्देश्य

  - ❖ शासन–प्रशासन तंत्र की आवश्यकताओं व जन अपेक्षाओं के अनुरूप परिवीक्षाधीन अधिकारियों की क्षमताओं और प्रबन्ध कौशल को विकसित करना।
  - ❖ प्रदेश की विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के बीच सामंजस्य एवं सौहार्द स्थापित करना।
  - ❖ प्रतिभागियों को सरकारी कार्य प्रणाली में लागू सिद्धातों और कार्य–प्रणालियों से परिचित कराना।
  - ❖ प्रतिभागियों को सरकारी प्रणाली में प्रबन्ध सम्बन्धी प्रक्रियाओं और तकनीकों से परिचित कराना।
  - ❖ प्रतिभागियों को लोक प्रशासन में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवेश की चुनौतियों के विश्लेषण व समाधान की क्षमता विकसित करने में सहायता करना।

- ## पाठ्यक्रम

आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् परिवीक्षाधीन अधिकारियों से निम्नलिखित क्षेत्रों में दक्षतापूर्वक कार्य करने की अपेक्षाएँ की जाती हैः–

  - ❖ संविधान, सेवा नियम तथा अनुशासनिक कार्यवाही।
  - ❖ लोक संसाधन एवं संगठनात्मक व्यवहार।
  - ❖ विधि एवं विधि व्यवहार।
  - ❖ वित्त एवं लेखा।
  - ❖ कार्यालय प्रबन्ध एवं प्रक्रिया।

- ❖ प्रबन्ध एवं मानव संसाधन विकास।
- ❖ विकास, ग्राम विकास, नगर विकास एवं विकेन्द्रीकृत नियोजन तथा कम्प्यूटर दक्षता।
- ❖ क्षेत्र एवं अध्ययन भ्रमण।

आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम अकादमी बैनर डिवीजन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थी अधिकारियों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है।

● सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनाँक 17 जनवरी, 2003 को प्रेषित पत्र (संख्याः 1833 एक–1–2003) द्वारा राज्य के समस्त विभागों एवं अकादमी, नैनीताल को यह सूचित किया गया था कि **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग** से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को (राज्य स्तरीय सेवाओं से भिन्न) कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अनिवार्य रूप से आधारभूत/सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कोर्स अकादमी, नैनीताल में प्राप्त करना होगा जिससे कि नवचयनित अधिकारियों को उनकी सेवाओं से सम्बन्धित कर्त्तव्यों एवं दायित्वों से परिचित कराया जा सके। एक माह के सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कोर्स का संचालन 09 माड्यूलों के अन्तर्गत किया जाता है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नवचयनित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से दिया गया उपरोक्त आदेश/पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कि नव–नियुक्त लोक सेवकों से जन अपेक्षाओं के संदर्भ में अधिक संवेदनशील एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। शासन तंत्र द्वारा इस सम्बन्ध में अनेकों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल की गई है। तेजी से बदलते हुए परिवेश में, विशेषकर उत्तराखण्ड की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध अवसरों, समस्याओं एवं चुनौतियों के संदर्भ में, समस्त नव–नियुक्त अधिकारियों से संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों एवं सिद्धान्तों, लोकतान्त्रिक मूल्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते हुए विशेषज्ञतापूर्ण सेवायें प्रदान करने की अपेक्षा की जा रही हैं। उपरोक्त अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं के क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय को फलीभूत करने के उद्देश्य के साथ अकादमी, नैनीताल द्वारा नव–नियुक्त पशु चिकित्साधिकारियों एवं चिकित्साधिकारियों हेतु भी एक माह के **'सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम'** अकादमी में आयोजित किए जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के समूह 'ख' तथा 'ग' के समस्त ऐसे अधिकारियों/कार्मिकों जिनके द्वारा सेवा में प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का सेवा प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है, के लिए एक माह का अनिवार्य सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पूर्व से सेवारत् अधिकारियों/कार्मिकों हेतु मिड कैरियर प्रशिक्षण डा0 आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के माध्यम से आयोजित किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या : 450/ XXX (2)/ 2014, दिनाँक : 03 नवम्बर, 2014 जारी किया गया है।

सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य निम्नांकित हैंः–

- ❖ उत्तराखण्ड की सामाजिक, आर्थिक एव सांस्कृतिक परिस्थितियों से नव–नियुक्त अधिकारियों को परिचित कराना।

- ❖ नव–नियुक्त अधिकारियों को एक कुशल लोक–सेवक की भूमिका के निर्वहन करने हेतु उनमें प्रबन्धन एवं प्रशासकीय क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करना।
- ❖ विकास में विशेषज्ञतापूर्ण, प्रशासनिक एवं मानवीय मूल्यों की आवश्यकता एवं महत्व की समझ के विकास के अवसर प्रदान करना।
- ❖ सूचना तकनीकी के वर्तमान परिवेश में महत्व, योग सम्बन्धित जानकारी से अवगत कराना एवं आवश्यक सम्बन्धित क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करना।

आलोच्य वर्ष 2019–2020 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नवागत राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों एवं कार्मिकों हेतु विभिन्न सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजपत्रित श्रेणी के अंतर्गत अकादमी में आयोजित किए जाने वाले सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संदर्भ में आलोच्य वर्ष में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों हेतु **इकतालीसवाँ सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम,** सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत सहायक अभियंताओं हेतु **बयालीसवाँ सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम** सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अराजपत्रित श्रेणी के अंतर्गत उत्तराखण्ड सचिवालय में नवनियुक्त समीक्षा अधिकारियों/सहायक समीक्षा अधिकारियों हेतु **उनतालीसवाँ, चालीसवाँ एवं इकतालीसवाँ सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम,** परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड में नवनियुक्त परिवहन कर अधिकारी–02 हेतु **बयालीसवाँ सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम** तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में नवनियुक्त समीक्षा अधिकारियों/सहायक समीक्षा अधिकारियों हेतु **तैंतालीसवाँ सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों हेतु कुल 04–सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

(2) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सहायता से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए चिन्हित आवश्यकता आधारित विभिन्न विषयों पर एक सप्ताह एवं तीन दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण आलोक में अकादमी ने प्रशिक्षकों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। तद्नुसार प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम में मुख्य रूप से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है जो प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल विकसित करने में सहायक है। तद्नुसर अकादमी द्वारा प्रत्यक्ष प्रशिक्षक कौशल, डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग,इवैल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग तथा मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग इत्यादि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश एवं देश में कार्यरत प्रशिक्षकों हेतु किया जाता है। आलोच्य वर्ष 2019–20 में इसके अन्तर्गत कुल 35 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 894 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(5) विभागीय परीक्षाएँ

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अकादमी को उत्तराखण्ड शासन के अधीन कार्यरत विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु विभागीय परीक्षाओं के आयोजन का दायित्व भी सौंपा गया है। शासनादेश संख्या 2858/XXX(ii)/2005 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने तथा पदोन्नति

के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर कतिपय पदों के संबंध में संबंधित सेवा नियमावलियों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है। राज्य गठन से पूर्व ऐसी विभागीय परीक्षाओं का आयोजन अध्यक्ष विभागीय परीक्षा एवं आयुक्त इलाहाबाद मंडल द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया जाता था, परन्तु वर्ष 2005 से उत्तराखण्ड राज्य की समस्त सेवाओं एवं पदों पर विभागीय परीक्षा का आयोजन डा0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा किया जा रहा है।

आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ

परिचय

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से जनवरी 1995 में उत्तर प्रदेश प्रशासन अकादमी, नैनीताल में ''आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ'' का गठन राज्य स्तर पर एक इकाई के रूप में किया गया था। जून 2002 में आपदा प्रबंध प्रकोष्ठ को कृषि मंत्रालय से हस्तानान्तरित कर मानव संसाधन मंत्रालय को सौंप दिया गया था। जुलाई 2004 से 2006 तक इस इकाई को आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केन्द्र, देहरादून में स्थानान्तरित कर दिया गया था पुनः जुलाई 2006 में आपदा प्रकोष्ठ को डा0 रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में स्थानांतरित किया गया तथा तब से आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ डा0 रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी की एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा हैः–

आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के/लक्ष्य/उद्देश्य/कार्य

- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता विकास करना।
- कौशल और ज्ञान का प्रसार करना तथा विभिन्न क्षेत्रों से विभागीय अधिकारियों विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्र से स्वयं सेवकों एवं क्षेत्र प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना।
- ''एक तैयार समुदाय एक सुरक्षित समुदाय है'' अतः आपदा प्रबंधन हेतु विभिन्न समुदायों को प्रशिक्षित कर सम्बन्धित उत्तरदायित्वों को सरकार से समुदायों की तरफ हस्तांतरित करने हेतु ध्यान केन्द्रित करना।
- उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य पर्वतीय राज्यों में आपदाओं के मूल कारणों के समाधान को खोजना पूर्व में घटित घटनाओं का आलेख तैयार कर भविष्य की रणनीति तैयार करना।
- आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित केस स्टडीज (अध्ययनों) का प्रलेखीकरण तथा उसके अनुरूप प्रशिक्षार्थियों एवं अन्य लाभ प्राप्तकर्ताओं हेतु साहित्य का प्रकाशन।
- आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न संस्थानों हेतु अलग–अलग विषयों पर मॉड्यूल तैयार कर जैसे जेण्डर एवं आपदा प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक सुझाव एवं प्राथमिक सहायता, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं भूकम्प सुरक्षित निर्माण विषयक मॉड्यूल अग्रिम कार्यशालाओं हेतु तैयार किया जाना।
- राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा योजना के अन्तर्गत विद्यालय सुरक्षा हेतु मॉड्यूल तैयार किया जाना ताकि समय–समय पर विद्यार्थियों को मॉकड्रिल एवं अभ्यास के माध्यम से जागरूक तथा संवेदनशील किया जा सके।
- विभिन्न शासकीय रेखीय विभागों के अधिकारियों हेतु समय–समय पर प्राकृतिक आपदा के विभिन्न पहलुओं के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं को आयोजित करना जैसे – जंगल की आग, खोज

बचाव, प्राथमिक सहायता, विद्यालय सुरक्षा, मानसिक विकार, तनाव प्रबंधन, भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण तकनीक।

- ❖ विकास खण्ड/तहसील स्तर पर संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- ❖ विद्यालयी छात्र–छात्राओं सहित जनचेतना उत्पन्न करने के उद्वेश्य से अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर विशेष वार्ताओं, निबन्ध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।
- ❖ भूकम्प, भूस्खलन, भूक्षरण, बाढ़, सूखा, बादल फटना, वनाग्नि, आग एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध कार्य करना तथा विस्फोटकों द्वारा मानवकृत आपदाओं से बचाव हेतु जागरूकता पैदा करना।
- ❖ प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन हेतु पठन सामग्री जैसे भूकम्प, भूस्खलन, अग्नि सुरक्षा, प्राथमिक सहायता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आदि का सम्पादन एवं प्रकाशन का विकास करना।

इस प्रकोष्ठ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यशाला/गोष्ठी/सेमिनार/प्रशिक्षण का आयोजन कर प्राकृतिक आपदाओं मानवकृत आपदाओं के विभिन्न पहलुओं (योजना, राहत कार्य, पुर्नवास आदि) के प्रति जनचेतना लाने का प्रयास करना तथा इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य सरकारी एवं गैर सरकारी के साथ–साथ राज्य के अन्य अधिकारियों के लिए विविध क्षेत्रों में सेवाकालीन प्रशिक्षण आरम्भ किये गये और विभिन्न क्षेत्रों में शोध सम्बन्धी गतिविधियों को भी आरम्भ किया गया। अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाना/जागरूकता पैदा करना है। साथ ही प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाओं से सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन व विश्लेषण करना तथा समय–समय पर उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिवों, सचिव व आपदा प्रबंधन एवं पुर्नवास विभाग को आपदा प्रबंध को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु सुझाव प्रेषित करना भी प्रकोष्ठ का महत्वपूर्ण कार्य है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में आयोजित प्रशिक्षण/प्रकोष्ठ की विशिष्ट उपलब्धियाँ

- ❖ भूकम्प अवरोधी डेमों यूनिट की स्थापना अकादमी परिसर में की जानी है, इस हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, देहरादून से सहमति प्राप्त हो चुकी है। सम्भवतया वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस डेमो यूनिट को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- ❖ **प्रकाशन**
  - ➢ Earthquake (Booklet)
  - ➢ Compendium (Lectures given by Specialists 2015-17)

संचालित विभिन्न नवीन गतिविधियों का विवरणः–

- ❖ Hospital Disaster Management Action Planराष्ट्रीय स्तर की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से Post Disaster Needs Assessment राष्ट्रीय स्तर की तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- 14वें आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में 28 जनवरी से 02 फरवरी 2020 तक देहरादून के विभिन्न संस्थानों में अध्ययन भ्रमण में सहभागिता।
- भूगर्भ विज्ञान, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा प्रायोजित दिनांक 25–27 सितम्बर, 2019 की अवधि में Climate Water and Environment अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में संकाय द्वारा बतौर समन्वयक के रूप में कार्यक्रम की गतिविधियों में सहयोग।
- आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल द्वारा प्रायोजित दिनांक 16–18 अक्टूबर 2019 की अवधि में Thirty Meter Telescope (TMT) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में संकाय द्वारा बतौर समन्वयक के रुप में कार्यक्रम की गतिविधियों में सहयोग।
- दिनांक 27–28 फरवरी 2020 की अवधि में अकादमी में संचालित राष्ट्रीय कार्यशाला Water & Sanitation में प्रकोष्ठ से संकाय/कार्मिकों का सहयोग।
- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन, भारत सरकार, नई दिल्ली को Centre of Excellence on Landslide रू0 25.00 लाख का प्रस्ताव प्रेषित।

भविष्य की रणनीतियाँ/उद्देश्यः–

- डी.ओ.पी.टी. एवं राज्य द्वारा आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।
- राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों का आयोजन।
- डॉ.आर.एस.टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना तैयार करना।
- विभिन्न आपदाओं के लिये पाठ्य सामग्रियों का निर्माण करना।
- Standard Operation Procedure को तैयार करना।
- राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से समन्वय स्थापित करना।
- Webinar एवं Webex के तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना।

सेन्टरफॉर गुड गवर्नेन्स

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के अन्तर्गत सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स (सी0जी0जी0) एक स्वायत्तशासी एवं स्ववित्तपोषित संस्था के रूप में सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी है। सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स के संगठनात्मक अध्यक्ष के रूप में अकादमी निदेशक/महानिदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में, अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक पदेन सचिव के रूप में तथा संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक (वित्त) पदेन वित्त नियंत्रक के रूप में योगदान प्रदान करते हैं। सेन्टर फॉर गुड

गवर्नेन्स की स्थापना का मुख्य उद्‌देश्य परियोजना आधारित कार्यक्रमों का निष्पादन करना है। सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स (सी0जी0जी0) के मुख्य उद्‌देश्य निम्नवत् हैं:–

- ❖ शासकीय विभागों के साथ मिलकर माँग के आधार पर अभिशासन में सुधार के मुख्य बिन्दुओं को चिन्हित करना, उनका समाधान करना तथा कार्ययोजना तैयार करना एवं उस कार्ययोजना को लागू करवाना।
- ❖ राज्य तथा स्थानीय प्रशासन के साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अभिशासन में सुधार तथा प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में अभिकल्पन, शोध एवं कार्ययोजना बनाने तथा उन्हें लागू कराने में परामर्श एवं सुझाव देना।
- ❖ शासकीय सुधारों के क्षेत्र में अच्छे कार्यों का अध्ययन तथा उनको अभिलिखित करना, अभिशासन में सुधार तथा ई–गवर्नेन्स के क्षेत्र में अब तक हुए अच्छे कार्यों तथा सुधार के साधनों को संकलित करना।
- ❖ उन क्षेत्रों को चिन्हित करना जो सरकार के क्रियाकलापों तथा नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं तथा जिनसे जन अपेक्षाओं के अनुरूप बदलाव लाया जा सकता है।
- ❖ शासन के लक्ष्यों, उद्‌देश्यों तथा नीतिगत प्राथमिकताओं को ठोस सुधार के रूप में अनूदित करना तथा शासन के लिए थिंक–टैंक के रूप में कार्य करना।
- ❖ माँग के आधार पर विकासात्मक प्रशासन हेतु उपयुक्त अवसर सृजित एवं उपलब्ध कराना जिससे ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति तथा अनुभव का विकास एवं उच्चीकरण किया जा सके। सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स के अन्तर्गत निम्नलिखित सात परियोजना प्रबन्धन इकाईयाँ (Project Management Units) कार्यरत हैं :–

1.	प्रोजक्ट प्लानिंग एण्ड परफारमेन्स बजटिंग इकाई
2.	ई–गवर्नेन्स इकाई
3.	प्रलेखन एवं समन्वय इकाई
4.	नगरीय कार्य इकाई
5.	की–रिसोर्स सेन्टर : पेयजल एवं स्वच्छता
6.	बौद्धिक सम्पदा एवं मानवाधिकार इकाई
7.	जेन्डर इकाई

वर्तमान में निदेशक, डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं तथा संयुक्त निदेशक (प्रशासन), सचिव एवं उप– निदेशक (वित्त) द्वारा वित्त नियन्त्रक के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न इकाईयों में परियोजनाओं के संचालन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए समन्वयक तथा परियोजना प्रबन्धकों को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ के रूप में अनुबंधित किया गया है, जो अकादमी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के

सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स में कार्यरत संकाय सदस्यों को अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता एवं पर्याप्त अनुभव प्राप्त है तथा उनके द्वारा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके प्रशिक्षक के रूप में भी विशेषज्ञता प्राप्त की गई है।

(1) प्रोजक्ट प्लानिंग एण्ड परफॉरमेन्स बजटिंग इकाई

सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स के अन्तर्गत इस इकाई की स्थापना की गई है। इस इकाई का मुख्य कार्य शासकीय विभागों के साथ मिलकर माँग के आधार पर अभिशासन में सुधार के मुख्य बिन्दुओं को चिन्हित करना, समाधान करना तथा कार्ययोजना तैयार करना एवं उस कार्य योजना को लागू करवाना है। इसके अलावा यह इकाई राज्य तथा स्थानीय प्रशासन के साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अभिशासन में सुधार तथा प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में अभिकल्पन, शोध, एवं कार्ययोजना बनाने तथा उन्हें लागू कराने में परामर्श एवं सुझाव देने का कार्य भी करती है।

(2) ई–गवर्नेन्स इकाई

सूचना तकनीकी का प्रसार अप्रत्याशित गति से हो रहा है। सभी अभिकरणों एवं संस्थाओं को कम्प्यूटरीकृत करने की ओर अग्रसर होना आवश्यक हो गया हैं, साथ ही किसी भी स्तर के कार्मिक के लिये कम्प्यूटर पर कार्य करने की क्षमता एक पूर्वापेक्षा बन गई है। निर्णय प्रक्रियाओं के समय से सम्पादित होने के लिये आवश्यक है कि पूर्ण सूचनाएँ न्यूनतम समय में प्राप्त हो सकें, और इस रूप में प्राप्त हों कि उनका विश्लेषण यथासमय किया जा सके। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 1996 के अनुरूप सभी के लिये प्रशिक्षण तथा सरकारी कार्मिकों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण के उद्देश्य से इस पी.एम.यू. द्वारा प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। साथ ही इकाई सॉफ्टवेयर विकास, कम्प्यूटरीकरण तथा कम्प्यूटर अवस्थापनाओं के सम्बन्ध में एक परामर्शदाता की भूमिका का भी सक्रियता से निर्वहन करती है। सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स के अन्तर्गत गठित ई–गवर्नेन्स इकाई के द्वारा प्रति वर्ष कम्प्यूटर एप्लीकेशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के न केवल अधिकारीगण वरन अन्य कार्मिकों को भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विशेषता यह है कि इनमें कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कार्यप्रणाली के प्रशिक्षण के साथ ही की–बोर्ड उपयोग की तकनीकी और हिन्दी में सभी प्रकार के कार्य करने की विधियों पर विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। परिचर्चाओं के दौरान सम्बन्धित विभागों के कम्प्यूटरीकरण पर भी परामर्श दिया जाता है।

(3) प्रलेखन एवं समन्वय इकाई

सूचना का संकलन और संप्रेषण डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल की एक प्रमुख गतिविधि है, अतः सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं व कार्यक्रमों की गतिविधियों के सुव्यवस्थित अभिलेखन हेतु प्रलेखन इकाई की स्थापना की गई है। इसके संचालन का दायित्व पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र को सौंपा गया है। प्रलेखन इकाई द्वारा सेन्टर फार गुड

गवर्नेन्स की विभिन्न गतिविधियों व कार्यक्रमों के अभिलेखीकरण में गुणवत्ता व एकरूपता बनाये रखने के साथ–साथ प्रकाशन हेतु परामर्श व तकनीकी सहायता भी दी जाती है तथा विभिन्न प्रलेखों के प्रकाशन, विक्रय और रखरखाव का भी कार्य किया जा रहा है। प्रलेखन इकाई द्वारा प्रकाशनों को अलग–अलग श्रृंखला के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों को प्रकाशित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश के अधिकारियों में विवेचन तथा विचारों का प्रवाह होता रहे। सी.जी.जी. द्वारा प्रकाशित विभिन्न साहित्य के मुद्रण, सम्पादन व विक्रय की सम्पूर्ण व्यवस्था का समन्वय पी.एम.यू. प्रलेखन द्वारा सम्पादित किया जाता है। स्थापना से लेकर अब तक 90 से अधिक प्रलेखों का प्रकाशन व वितरण किया गया है। प्रलेखन इकाई द्वारा अकादमी में स्थापित फोटो कॉपियर मशीन का अनुबन्ध मैसर्स मोदी जिरौक्स के साथ कर फोटोकापी कार्य पर नियन्त्रण तथा मशीनों के रख–रखाव तथा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। यह सभी कार्य सशुल्क किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त प्रति वर्ष विभिन्न विभागों/संस्थाओं इत्यादि द्वारा माँग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला इत्यादि अकादमी में निरन्तर रूप से आयोजित किये जाते रहते हैं, जिनके समन्वय एवं संचालन का कार्य प्रलेखन एवं समन्वय इकाई के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी, सी0जी0जी0 अथवा अकादमी निदेशक/सीईओ महोदय द्वारा नामित संकाय अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(4) शहरी विकास प्रकोष्ठ

इस प्रकोष्ठ की परिकल्पना एवं स्थापना शहरी विकास तथा प्रबन्धन के सन्दर्भों में मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण, शोध एवं अभिलेखन गतिविधियों के आयोजन तथा विशेषज्ञतापूर्ण परामर्शदात्री इकाई के रूप में की गयी। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नगरीय प्रबन्धन में बढ़ती भूमिका तथा नगरीय प्रबन्धन से जुड़े विभिन्न कार्यदायी विभागों, अभिकरणों व संस्थानों के अधिकारियों व कार्मिकों सहित निर्वाचित शहरी निकाय प्रतिनिधियों के लिये क्षमता संवर्धन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1995 में शहरी विकास प्रकोष्ठ का गठन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम 'हड्को' के मानव बसाव प्रबन्धन संस्थान (एच.एस.एम.आई.), नई दिल्ली के सहयोग से उत्तर प्रदेश (अब उत्तराखण्ड) प्रशासन अकादमी, नैनीताल स्थित सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट स्टडीज के अन्तर्गत किया गया था। एच.एस.एम.आई. द्वारा इसी उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों में स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों में ''हडको चेयर्स'' की स्थापना की गयी है। प्रकोष्ठ को पूर्व में परियोजना प्रबन्धन इकाई–नगरीय कार्य का नाम दिया गया था। सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट स्टडीज की गतिविधियां समाप्त होने के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन की सहमति पर अप्रैल, 2005 से हड्को चेयर की गतिविधियों को अकादमी अन्तर्गत सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स के अन्तर्गत नियमित करते हुए संचालित किया जा रहा है। प्रकोष्ठ के अनुबन्ध को आगामी तीन वर्षों के लिये विस्तारण हेतु प्रक्रिया की जारही है। प्रकोष्ठ के अनुबन्ध विस्तारण हेतु HUDCO-HSMI से प्राप्त पत्र में प्रस्ताव मॉगा गया है जो संस्थान को भेजा जा चुका है। संस्थान द्वारा चेयर संचालन हेतु वार्षिक गतिविधियों पर आधारित अनुदान दिया जाता है।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Integrated Capacity Building Framework के अन्तर्गत शहरी विकास प्रकोष्ठ को राज्यों के शहरी निकायों एवं कार्यदायी संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में

क्षमता संवर्धन हेतु Empanelled Training entity के रूप में चयनित किया गया है। इसके अन्तर्गत शहरी विकास प्रकोष्ठ द्वारा निर्वाचित जन प्रतिनिधि/शहरी स्थानीय निकाय एवं कार्यदायी विभागों मे कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/अध्ययन भ्रमण इत्यादि का आयोजन के अतिरिक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं पाठ्य सामग्री का निर्माण करने का कार्य भी किया जा रहा है। प्रकोष्ठ का NIUA द्वारा विकेन्द्रीकृत स्वच्छता समाधान को स्थापित करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के शहरी विकास एवं कार्यदायी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु शहरी विकास प्रकोष्ठ (सी.जी.जी.) उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी के साथ अनुबंध किया गया है,जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020/21 के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाने है।

शहरी विकास प्रकोष्ठ के लक्ष्य/उद्देश्य एवं कार्य :—

प्रकोष्ठ का प्रमुख लक्ष्य शहरी विकास एवं प्रबन्धन के उद्देश्य से विभिन्न विभागों/संस्थानों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिये जाने हेतु शहरी स्थानीय निकायों, विभिन्न कार्यदायी विभागों तथा अभिकरणों में प्रदेश स्तर से कटिंग—एज स्तर पर कार्यरत अधिकारियों, कार्मिकों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों में ज्ञान तथा कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमता विकास आवश्यकताओं की पूर्ति करना रखा गया है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नांकित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :

- ❖ प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आवासीय, शहरी विकास एवं प्रबन्धन के कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने में शहरी निकायों तथा अन्य कार्यदायी संस्थाओं को आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान करना तथा इस हेतु कार्यरत अधिकारियों, कार्मिकों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों में अपेक्षित ज्ञान तथा कौशल विकास हेतु क्षमता विकास कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन।
- ❖ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा नगरीय सुधारों के सन्दर्भ में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिकाओं को समृद्ध किये जाने हेतु प्रयास।
- ❖ उपरोक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सहायक गतिविधियों जैसे शोध, प्रलेखन, प्रशिक्षण, पाठ्क्रमों का विकास तथा प्रसार करना आदि।
- ❖ नगरीय विकास एवं इससे सन्दर्भित क्षमता विकास कार्यों को बढ़ाये जाने एवं बेहतर गुणवत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के साथ सम्पर्क स्थापना (नेटवर्किंग) करना।

उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रकोष्ठ द्वारा मुख्य रूप से निम्नांकित गतिविधियों का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है:

- ❖ शहरी विकास तथा प्रबन्धन हेतु कार्यरत विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के क्षमता विकास को लक्षित करते हुए प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन एवं तद्नुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन व संचालन।
- ❖ आवश्यकता आधारित एवं लक्ष्य पूर्तिपरक प्रशिक्षण पाठ्क्रमों का विकास जिनमें ज्ञान व कौशल विकास के साथ ही अभिवृत्ति परिवर्तन भी समावेशित है।

- ❖ चतुर्मुखी व व्यवस्थापरक सिद्धान्त प्रशिक्षण कार्यशैली।
- ❖ संस्थागत बहुलवाद एवं पारस्परिक सहयोग की दिशा में प्रयास।
- ❖ शासन, कार्यदायी विभागों, संस्थाओं, संगठनों, स्थानीय निकायों, जनता तथा विषय विशेषज्ञों के मध्य परस्पर समन्वय कार्य तथा शासन व स्थानीय प्रशासन को नीति व रणनीति बनाने में अपेक्षानुसार सहायता / सलाह प्रदान करना।
- ❖ महिलाओं एवं शहरी गरीबों के सशक्तीकरण सम्बन्धी प्रयास तथा इनके विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों में भागीदार अधिकारियों व कार्मिकों के क्षमता संवर्धन हेतु प्रयास।
- ❖ शोध कार्य जो क्षमता विकास तथा लोकहित से सन्दर्भित व सम्बन्धित हों।
- ❖ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी विकास के क्षेत्र में किये जा रहे बेहतर व सफल प्रयासों का प्रलेखन व प्रसार।
- ❖ शहरी विकास से जुड़े हुये समस्त अधिकारियों को सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन पर कौशल प्रदान करना।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में इकाई / प्रकोष्ठ की उपलब्धियॉं :

- ❖ भारत सरकार को शहरी विकास की क्षमता संवर्धन कार्यक्रम (ICB Programme) के विभिन्न शहरी मिशन जैसे PMAY, NULM, AMRUT, इत्यादि की एकीकृत क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण के लिए शहरी विकास को Training entity के रूप में Empanel किया गया है।
- ❖ NIUA द्वारा विकेन्द्रीकृत स्वच्छता समाधान को स्थापित करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के शहरी विकास एवं कार्यदायी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु शहरी विकास प्रकोष्ठ (सी.जी.जी.) उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी के साथ अनुबंध किया गया है।
- ❖ शहरी विकास प्रकोष्ठ सी.जी.जी. डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल एवं उत्तराखण्ड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच अनुबन्ध किया जा चुका है, एवं अन्य प्रदेशों से अनुबन्ध किये जाने की प्रक्रिया जारी है।
- ❖ प्रकोष्ठ के अनुबन्ध को आगामी तीन वर्षों (2019–2022) के लिये विस्तारण हेतु प्रक्रिया की जा रही है। प्रकोष्ठ के अनुबन्ध विस्तारण हेतु HUDCO-HSMI से प्राप्त पत्र में प्रस्ताव मॉंगा गया है, जो संस्थान को भेजा जा चुका है। संस्थान द्वारा चेयर संचालन हेतु वार्षिक गतिविधियों पर आधारित अनुदान दिया जाता है।
- ❖ प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग (डी.ओ.पी.टी.), नई दिल्ली द्वारा 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम की संस्तुति प्राप्त हुई थी। जो प्रकोष्ठ द्वारा पूर्ण कर लिये गये है।
- ❖ वर्ष 2019–20 में Ministry of Environment, Forest & Climate Change,Govt. of India, New Delhi (MOEF & CC) नई दिल्ली द्वारा प्रायाजित "Good Governance" विषय पर IFS अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गये।

❖ प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग (डी.ओ.पी.टी.), नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम शहरी विकास विषयक कार्यक्रम डी.ओ.पी.टी. को भेजे गये हैं।

संचालित विभिन्न नवीन गतिविधियों का विवरण :

❖ National Institute of Urban Affairs (NIUA) नई दिल्ली, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय,(MoHUA) भारत सरकार की एक रिर्सच संस्था है। NIUA द्वारा विकेन्द्रीकृत स्वच्छता समाधान को स्थापित करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के शहरी विकास एवं कार्यदायी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु शहरी विकास प्रकोष्ठ (सी.जी.जी.) उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी के साथ अनुबंध किया गया है, जिसके अन्तर्गत 09 प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाने है एवं Activity PlanNIUA को भेजा गया है।

❖ Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) के एकीकृत क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के लिये शहरी मिशन (PMAY,NULM) के कार्यक्रम किये जाने प्रस्तावित है।

❖ HUDCO, HSMI, नई दिल्ली, के साथ दूरभाष के वार्ता के क्रम मे अकादमी के साथ 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाने प्रस्तावित है।

❖ प्रकोष्ठ द्वारा प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग (डी.ओ.पी.टी.), नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम शहरी विकास विषय पर भेजे गये हैं।

(5) की–रिसोर्स सेन्टर (पेयजल एवं स्वच्छता इकाई)

की–रिसोर्स सेन्टर, (पेयजल एवं स्वच्छता) की स्थापना अप्रैल 2005 में पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार जो वर्तमान में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में सहयोग से उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में की गयी। की रिसोर्स सेन्टर द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से देश के समस्त राज्यों में क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, शोध एवं अध्ययन कार्य किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये स्वच्छता कार्यक्रम को केन्द्रीय मानते हुए वर्ष 2008 में अर्न्तराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष के रूप में मनाया गया पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की रिसोर्स सेन्टर, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल को मुख्य एजेन्सी के रूप में चिन्हित किया गया।

उद्देश्य

❖ पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में अध्ययन, मूल्यॉकन, समीक्षा एवं शोध कार्यों का प्रस्ताव बनाना तथा क्रियान्वित करना।

- ❖ पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों पंचायत राज संस्थाओं तथा व्यक्तिगत सलाहकारों के लिए क्षमता संवर्धन की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को चिन्हित करना।
- ❖ आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।
- ❖ राज्यों में कार्यरत कम्युनिकेशन एण्ड कैपेसिटी डेवलपमेंट यूनिट्स (सी.सी.डी.यू.) को तकनीकी मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ❖ पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में राज्य स्तरीय मानव संसाधन विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार की रणनीति तथा कार्ययोजना विकसित करना।
- ❖ पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर हेतु कार्यशालाएँ, सेमिनार, सम्मेलन आयोजित करना।

की रिसोर्स सेन्टर, पेयजल एवं स्वच्छता के कार्य पर क्षमता संवर्धन गतिविधियाँ

- ❖ की रिसोर्स सेन्टर द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा आरम्भ किये गये स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न राज्यों में पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में कार्य कर रहे विभिन्न विभागों के अभियन्ताओं, प्रबन्धकों, सलाहकारों के क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

- ❖ की रिसोर्स सेन्टर द्वारा देश के चार राज्यों– उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड एवं आसाम हेतु विश्व बैंक पोषित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.) के अन्तर्गत क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के लिये प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी इन राज्यों में किया गया।

- ❖ प्रकोष्ठ द्वारा भारत सरकार द्वारा चलायी जा रहे निर्मल भारत मिशन के अन्तर्गत National Workshop on Community-Led Approach in the context of Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें देश के लगभग सभी राज्यों ने प्रतिभाग कर स्वच्छता के क्षेत्र में व्यवहार परिवर्तन हेतु रणनीति तैयार की गयी।

- ❖ स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत देश के लगभग 15 राज्यों में व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- ❖ विश्व बैंक पोषित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हेतु प्रशिक्षण मैनुअल्स एवं थिमैटिक बुकलेट्स तैयार की गयी जिनका प्रयोग वर्तमान में उत्तर प्रदेश में संचालित पेयजल योजनाओं हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किया जा रहा है।

- ❖ प्रकोष्ठ द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजना, भारत सरकार के अन्तर्गत "SWAJAL – National Dissemination"विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें देश के पश्चिमी राज्यों में स्वजल परियोजना फेज–2 का शुभारम्भ किया गया।

- ❖ विश्व बैंक द्वारा उत्तराखण्ड शासन के सहयोग से स्वजल परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल विभिन्न क्षमता संवर्धन एवं नीति निर्धारण सम्बन्धी प्रशिक्षणों का आयोजन एवं योजना के प्रचार प्रसार हेतु आई.ई.सी. सामग्री तथा डाक्यूमैन्ट्री फिल्म इत्यादि तैयार करने का प्रस्ताव है।

- ❖ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अन्र्तगत विभिन्न बिन्दुओं पर राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन।

- ❖ प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत टी.डी.पी. एवं प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

की रिसोर्स सेन्टर, पेयजल एवं स्वच्छता इकाई द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर कार्यः

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये स्वच्छता कार्यक्रम को केन्द्रीय मानते हुए वर्ष 2008 में अन्र्तराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष के रूप में मनाया गया जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्व में स्वच्छता कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया। ग्राम्य विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र की उपरोक्त पहल को भारत के क्रियान्वित करने हेतु की रिसोर्स सेन्टर को मुख्य एजेन्सी के रूप में चिन्हित किया गया। इस क्रम में भारत वर्ष के समस्त 611 जनपदों से 02 नामित व्यक्तियों को समुदाय संचालित पहल पर सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षमता संवर्धन का दायित्व दिया गया, जिसे के0 आर0 सी0 द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका तथा महिला संगठनों को स्वच्छता की आदतों में सुधार हेतु मुख्य भूमिका में रखने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित की गयी, जिसमें सम्पूर्ण देश से 70 महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। उत्तर भारत के 14 सर्वाधिक पिछड़े हुए राज्यों के लिये के. आर. सी. ने मानव संसाधन एवं सूचना शिक्षा संचार की पॉच वर्षीय रणनीति को विकसित किया। इसी के अर्न्तगत यूनिसेफ के सहयोग से महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत नारी जागृति अभियान के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

विश्व बैंक पोषित स्वजल परियोजना हेतु उत्तराखण्ड राज्य के लिये राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य

की–रिसोर्स सेन्टर को पी एम यू–स्वजल, देहरादून द्वारा वर्ल्ड बैंक सहायतित परियोजना सेक्टरवाइड एप्रोच (स्वैप) के लिए उत्तराखण्ड राज्य में नोडल इकाई के रूप में चयनित किया गया है। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए के. आर. सी. को स्टेट लैवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत विगत वर्षो में के. आर. सी. द्वारा लगभग 40 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में समस्त स्तरों के लिये प्रशिक्षण मॉडयूल तथा प्रशिक्षण सामग्री भी के.आर.सी. द्वारा तैयार की गयी है। स्वजल परियोजना फेस–2 के अर्न्तगत आयोजित होने वाले समस्त क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों का समन्वय, रिपोटिंग एवं मूल्यांकन का दायित्व भी के. आर. सी. को सौपा गया।

विभिन्न संस्थाओ से नेटवर्किंग

के. आर. सी द्वारा ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता हेतु कार्य कर रही विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी विभागों/गैर सरकारी संगठनों/शोध संस्थाओं के साथ नॉलेज मैनेजमेन्ट हेतु नेटवर्किंग किया गया है। जैसे पेयजल मंत्रालय भारत सरकार, डब्लू.एस.पी. साउथ एशिया विश्व बैंक, कुमाऊॅं विश्व विद्याालय, नॉलेज लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनीसेफ, वाटर एड, आई.टी.आर.सी. लखनऊ, आई.डी.एस., हिमालयन स्टडी सर्किल पिथौरागढ़, रूरल इनिसिएटिवस फॉर सोशियल इंजीनियरिंग (राइज), सोसाइटी फॉर एक्शन इन माउन्टेनस विलेज इकोलाजिकल डेवलपमेन्ट एण्ड इनिशिएटिवस (संवेदी)।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में इकाई/प्रकोष्ठ की उपलब्धियाँ :

प्रकोष्ठ द्वारा जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से दिनांक 27 से 28 फरवरी, 2020 की अवधि में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत **"Provision of Potable Drinking Water in Mountains through Participatory Springshed Management"** विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारत के केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री भरत लाल, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, श्रीमती रूपा मिश्रा, निदेशक, जल जीवन मिशन एवं माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत के 22 राज्यों के अधिशासी अभियन्ताओं, हाइड्रोलॉजिस्ट तथा विभिन्न राज्यों के पेयजल विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों सहित 108 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

इकाई की भविष्य की रणनीतियाँ/उद्देश्य/प्रशिक्षण गतिविधियों सम्बन्धी जानकारियाँ :

- ❖ पी.एच.ई.डी. राजस्थान द्वारा स्वीकृत विभागीय अभियन्ताओं हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 04 क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- ❖ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- ❖ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 स्थायित्व एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं अध्ययन।
- ❖ डी.ओ.पी.टी. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।
- ❖ पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में मूल्यांकन एवं शोध कार्य किये जाने हैं।

(6) बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं मानवाधिकार इकाई

इस इकाई के अंतर्गत अकादमी तथा सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। आलोच्य वर्ष में इस इकाई द्वारा सूचना

का अधिकार अधिनियम–2005 पर कुल 04 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अयोजन किया गया तथा डी.ओ.पी.टी. भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कटिंग एज लेवल स्तर पर ग्रुप 'बी' अराजपत्रित एवं ग्रुप 'सी' कार्मिकों के लियेकुल 3 सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी उत्तराखण्ड के देहरादून व टिहरी जिलों में उक्त प्रकोष्ठ के माध्यम से सम्पादित कराया गया।

इकाई की भविष्य की रणनीतियाँ/उद्देश्य/प्रशिक्षण गतिविधियां

प्रकोष्ठ द्वारा भविष्य में प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे तथा DoPT भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित Improving Transparency and Accountability in Government through Effective Implementation of RTI Act-2005 परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा सेमीनार का आयोजन किया जायेगा तथा डी.ओ.पी.टी. भारत सरकार के सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

(4) जेण्डर इश्यूज प्रकोष्ठ

भारतीय संविधान की आत्मा सभी के लिए समानता तथा भेदभाव रहित समाज की रचना में ही बसती है। यद्यपि संविधान में जाति, धर्म, रंगभेद, के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पूर्ण व्यवहार को अस्वीकार किया है तथा अवसरों तक सभी की पहुँच के लिए समान अवसर प्रदान करने का प्राविधान है, किन्तु वास्तविकता में महिलाओं की आधी आबादी होने के बावजूद भी अवसरों तक उनकी पहुँच बहुत कम रही है। कारणों की पड़ताल करने पर स्पष्ट होता है कि, हमारे सामाजिक ढांचे में व्याप्त लैंगिक असमानता है, जो रीति–रिवाजों, रहन–सहन, घरेलू दिनचर्या तथा सामाजिक भूमिकाओं को तय करते समय दिखाई पड़ती है। इसी जेण्डर असमानता को दूर करने के उद्देश्य से सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के अन्तर्गत जेण्डर इश्यूज प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसके अन्तर्गत जिला, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं/एजेन्सियों में कार्यरत महिलाओं को क्षमता विकास प्रशिक्षणों के माध्यम से साामजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सुदृढ़ बनाने हेतु अग्रणीय प्रयास किये जा रहे हैं।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

- ❖ महिला सशक्तिकरण की सतत प्रक्रिया में महिलाओं का क्षमता विकास तथा शिक्षा, आर्थिक संसाधनों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाकर समाज में जेण्डर न्याय सहित समानता की स्वस्थ सोच का विकास करना प्रकोष्ठ का उद्देश्य है।
- ❖ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जीवन संतुलन के लाभों का समझना है।
- ❖ संतुलित जीवन शैली के लिए नियोक्ता संसाधनों के बारे में जानना।
- ❖ प्रभावी ढंग से दूरसंचार।
- ❖ अपने लिए प्रभावी कार्यविधियों का पता लगाना।

- ❖ लैंगिक समानता अपने आप में लक्ष्य है। यह समावेशी विकास और समाजों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण साधन है।
- ❖ प्रदेश की विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
- ❖ प्रतिभागियों को लोक प्रशासन में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवेश की चुनौतियों के विश्लेषण व समाधान की क्षमता विकसित करनें में सहायता करना।
- ❖ सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी प्रशिक्षण पर आधारित गुणों को एवं कौशल को विकसित करना जिससे वे कुशल प्रबन्धकों के रूप में अपने अधीनस्थों में कार्य क्षमताओं का विकास करना प्रकोष्ठ का उद्देश्य है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में इकाई /प्रकोष्ठ की विशिष्ट उपलब्धियाँ

राष्ट्रीय पोषण अभियान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य संसाधन समूह के सदस्यों को ILA (Incremental Learning Approach) मॉड्यूल का प्रशिक्षण केयर इण्डिया के प्रशिक्षकों द्वारा दिया गया। प्रशिक्षित प्रतिभागियों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल को जिला एवं ब्लॉक संसाधन समूहों के माध्यम से ऑगनवाड़ी कार्यकर्तियों तक पहुँचाया जायेगा। ILA (Incremental Learning Approach) के 21 मॉडयूल हैं जिनके द्वारा गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं एवं दो वर्ष तक के शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त विषयक 05 प्रशिक्षण कार्यक्रम अकादमी में सम्पन्न किये जा चुके हैं। वर्ष 2019–20 में दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- ❖ Status of Women in Panchayati Raj Institutions and Emerging Challenges–जेण्डर संवेदनशील प्रशिक्षण कार्यक्रम का उददेश्य प्रतिभागियों में जेण्डर संवेदी कार्यशैली का विकास करना तथा जेण्डर संवेदी परियोजना एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है जिसके द्वारा कार्य स्थलों में महिलाओं की कार्य क्षमता में विकास हो सके।
- ❖ Sensitization of Government Functionaries on Issues Relating to Minorities–भारत में अल्प संख्यक से संबंधित लोगो के अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे है, अल्पसंख्यक मुददों पर लगातार असहमति और चर्चा धार्मिक और राजनीतिक विवाद पैदा करती है। भारतीय संविधान ने हमें अल्पसंख्यको सहित सभी समुदायों को समान और निष्पक्ष अधिकार दिए जाने की वकालत की है, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित कुछ मुद्दों में कमी है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाकर प्रत्येक राज्य अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्कों के अधिकार उनके प्रांत के भीतर सुरक्षित हों। उपरोक्त विषयक दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- ❖ Gender Based Violence and Legal Safeguards–महिला के विरूद्ध हो रहे अपराधों को कम किया जा सके। पुलिस प्रशासन, न्याय प्रक्रिया एवं सिविल सोसाइटी से सहयोग एवं समन्वय द्वारा कार्यशैली में सुधार किया जा सकता है।

❖ उत्तराखण्ड राज्य के पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों हेतु 06 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रदेश तथा कार्यक्षेत्रों की समस्याओं को समाधान के लिए उनके आत्म विश्वास में वृद्धि करना है। जिससे वे अपने देश एवं प्रदेश के आवश्यकतानुसार कार्य करने के लिए तैयार करना।

भविष्य की रणनीतियाँ

❖ जेण्डर बजटिंग में इस वर्ष जेण्डर प्लानिंग को समाहित कर पंचायत प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को ग्रामीण स्तर पर ही जेण्डर रिस्पोंसिव बजट तथा प्लानिंग में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे।

❖ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं तथा अधिकारियों को व्यक्तित्व सुधार तथा कार्यक्षेत्र एवं पारिवारिक जीवन में संतुलन के तरीके बताये जायेंगे।

❖ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में इस विषय पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे तथा जेण्डर समानता को बढ़ावा देने तथा घटते हुए लिंगानुपात में सुधार लाने हेतु आवश्यक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

❖ इसके अतिरिक्त जेण्डर संवेदनशील शासन तथा जेण्डर संवेदनशील संगठनात्मक कार्य संस्कृति के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन एवं आयोजित किये जायेगे जिनसे काम काजी महिलाओं को कार्य करने हेतु अनुकुल वातावरण प्राप्त हो सके। भविष्य में प्रकोष्ठ द्वारा महिला उद्यमिता कौशल में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

❖ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 02 लंबित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु रणनीति बनायी जायेगी।

❖ उत्तराखण्ड राज्य के पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों हेतु लंबित एक 06 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा तथा प्रतिभागियों को कार्यक्षेत्रों की समस्याओं को समाधान के लिए उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करना है।

वर्ष 2019–20 में अकादमी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण गतिविधियों का चार्ट निरूपण

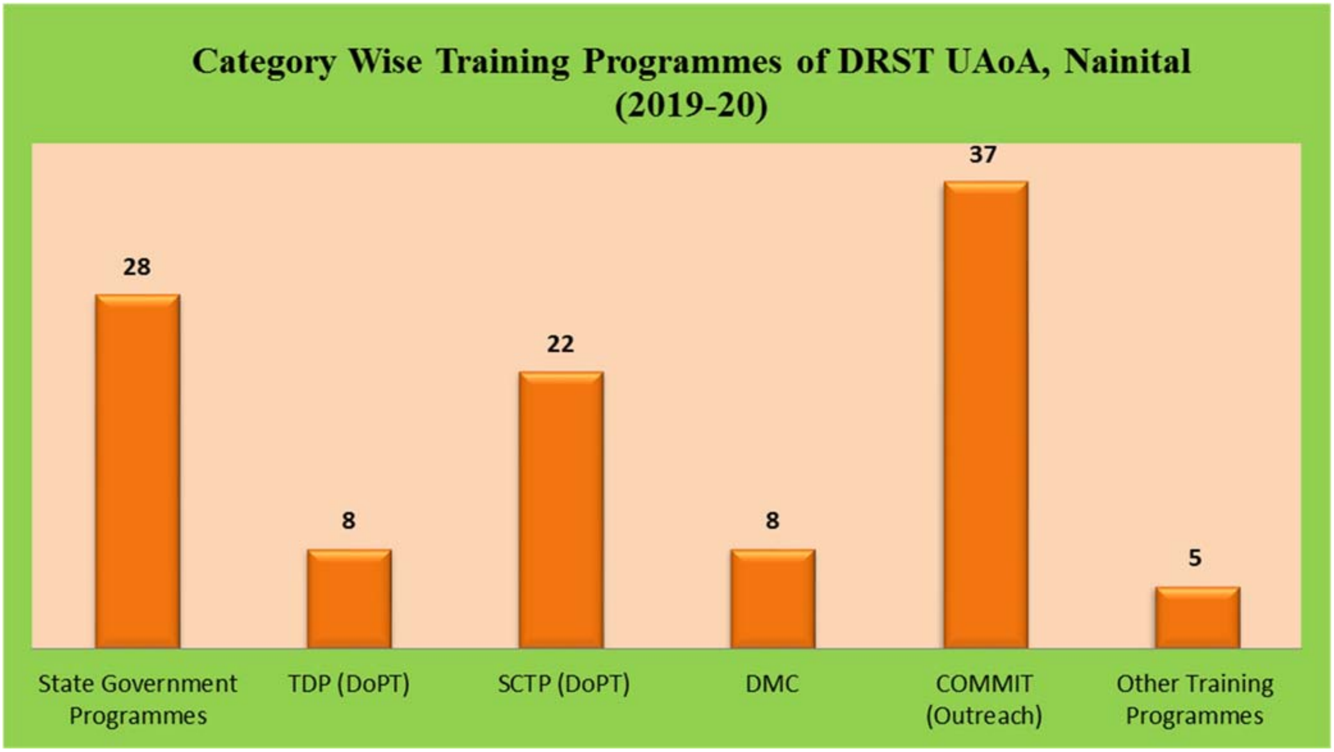
Category Wise Training Programmes of DRST UAoA, Nainital
(2019-20)
28
8
22
8
37
5
State Government Programmes
TDP (DoPT)
SCTP (DoPT)
DMC
COMMIT (Outreach)
Other Training Programmes

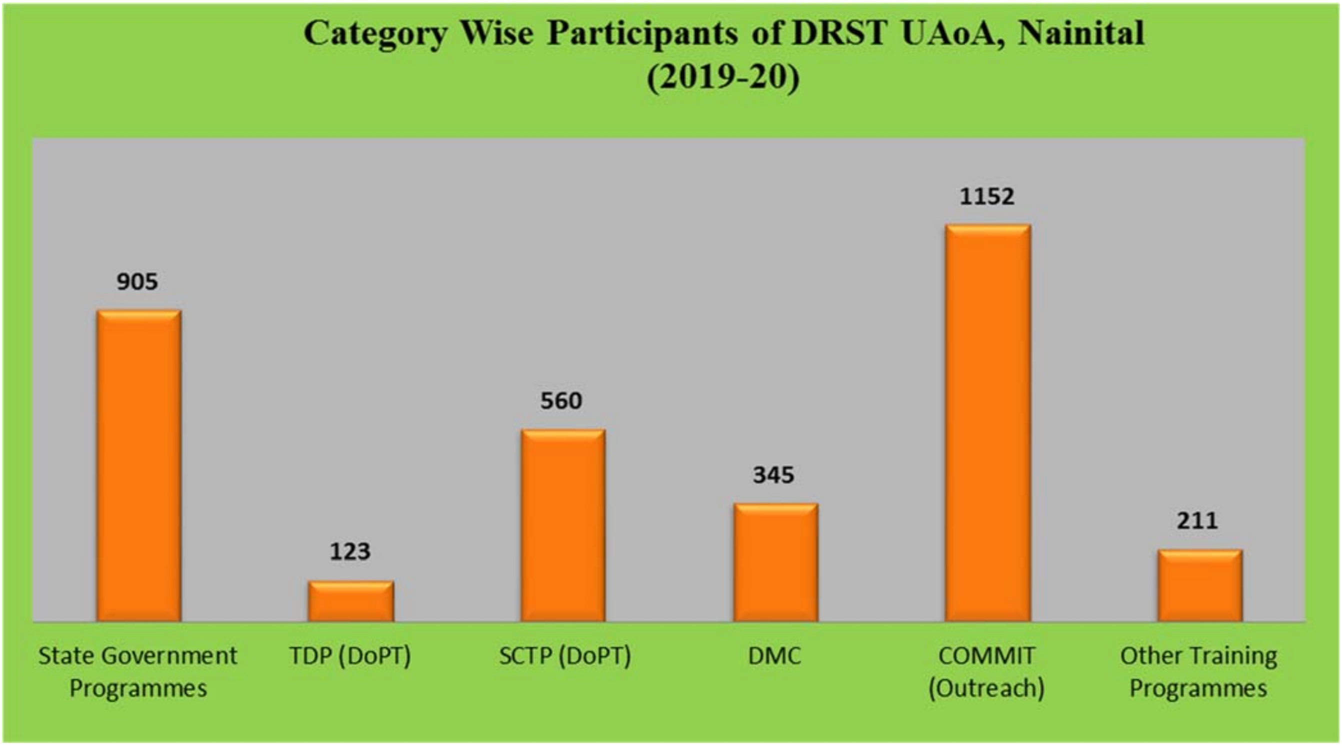
Category Wise Participants of DRST UAoA, Nainital
(2019-20)
905
123
560
345
1152
211
State Government Programmes
TDP (DoPT)
SCTP (DoPT)
DMC
COMMIT (Outreach)
Other Training Programmes

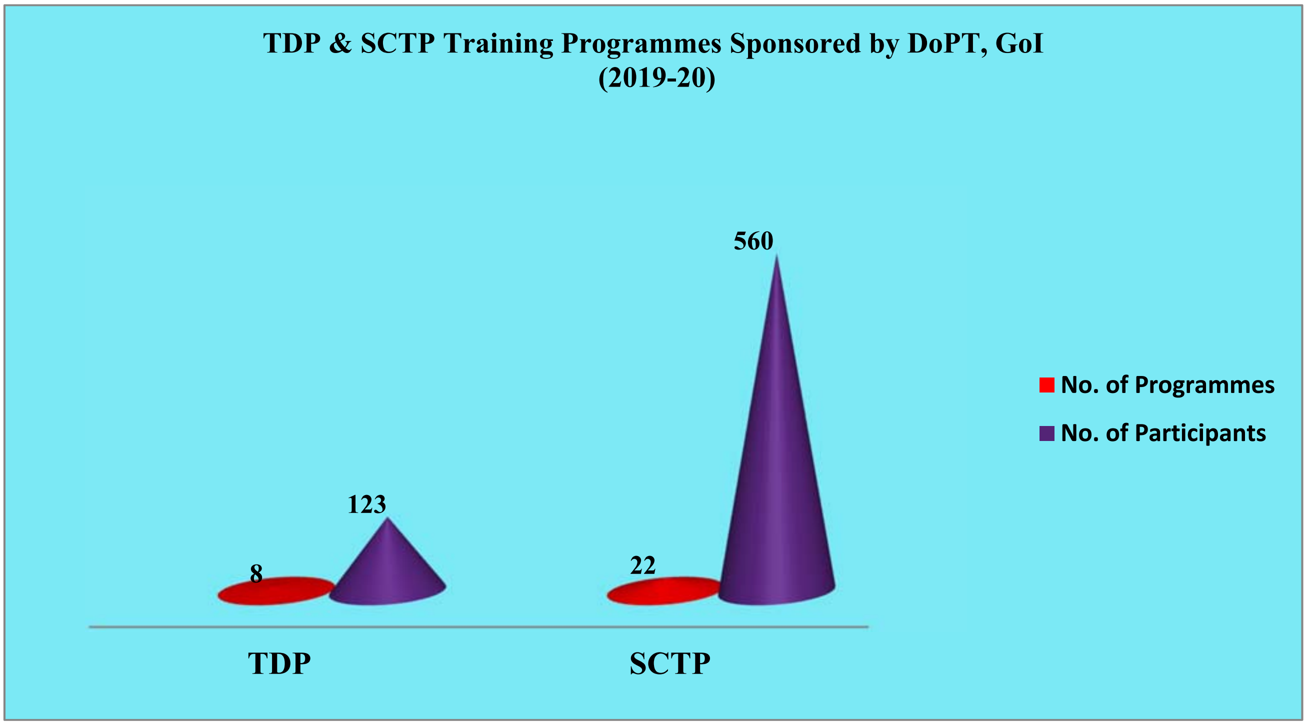
TDP & SCTP Training Programmes Sponsored by DoPT, GoI
(2019-20)
560
123
8
22
TDP
SCTP
No. of Programmes
No. of Participants

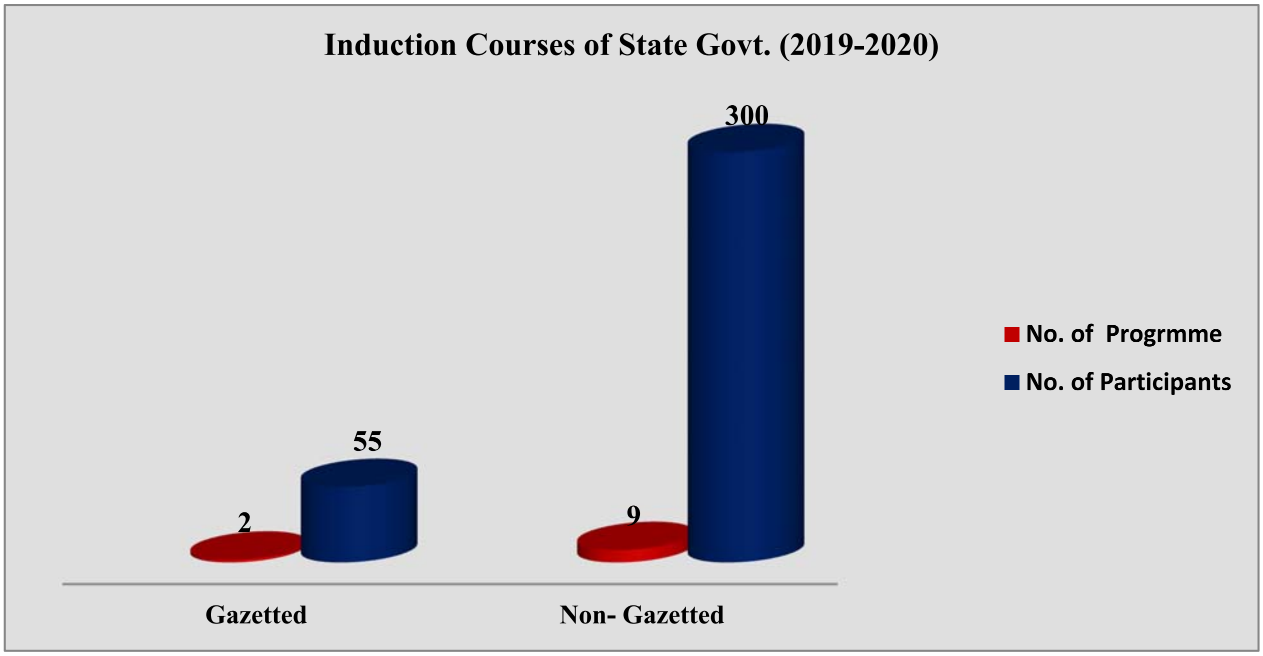
Induction Courses of State Govt. (2019-2020)
300
55
2
9
Gazetted
Non- Gazetted
No. of Progrmme
No. of Participants

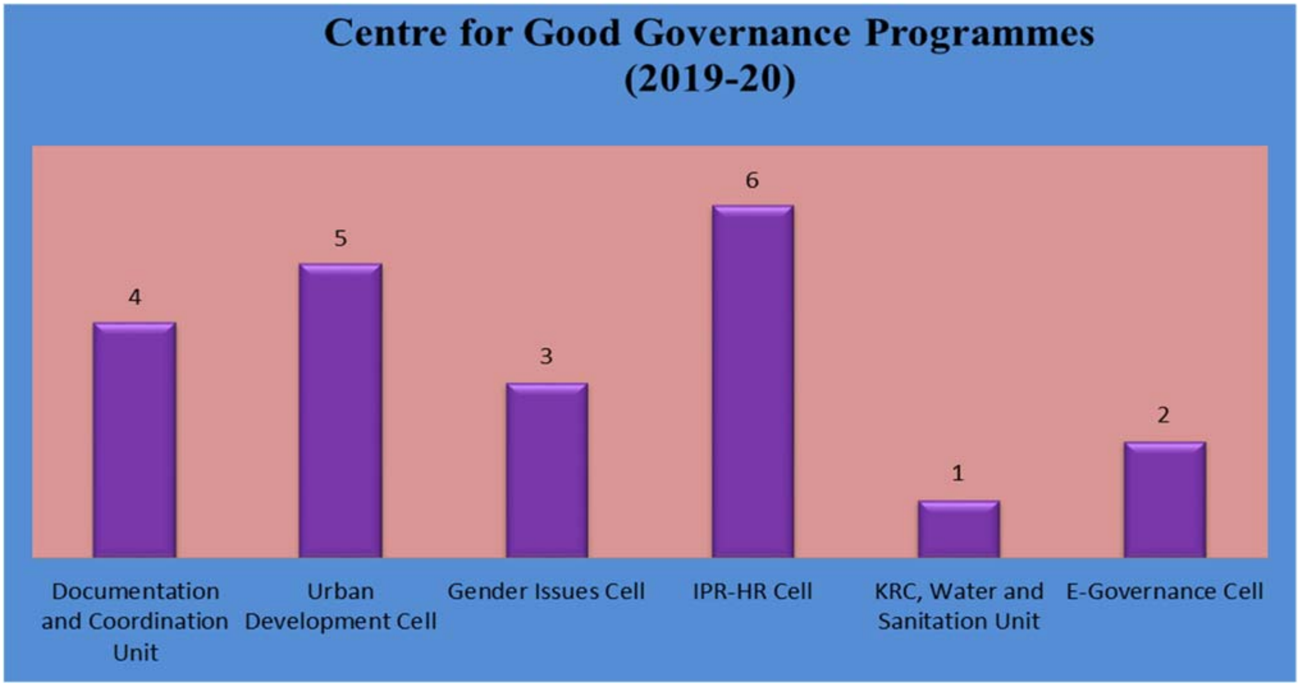

Dr. RST UAoA (Dr. R.S.Tolia Uttarakhand Academy of Administration)	**108 Programmes**
CGG (Centre for Good Governance)	**21 Programmes**
Total Programmes	**129 Programmes**

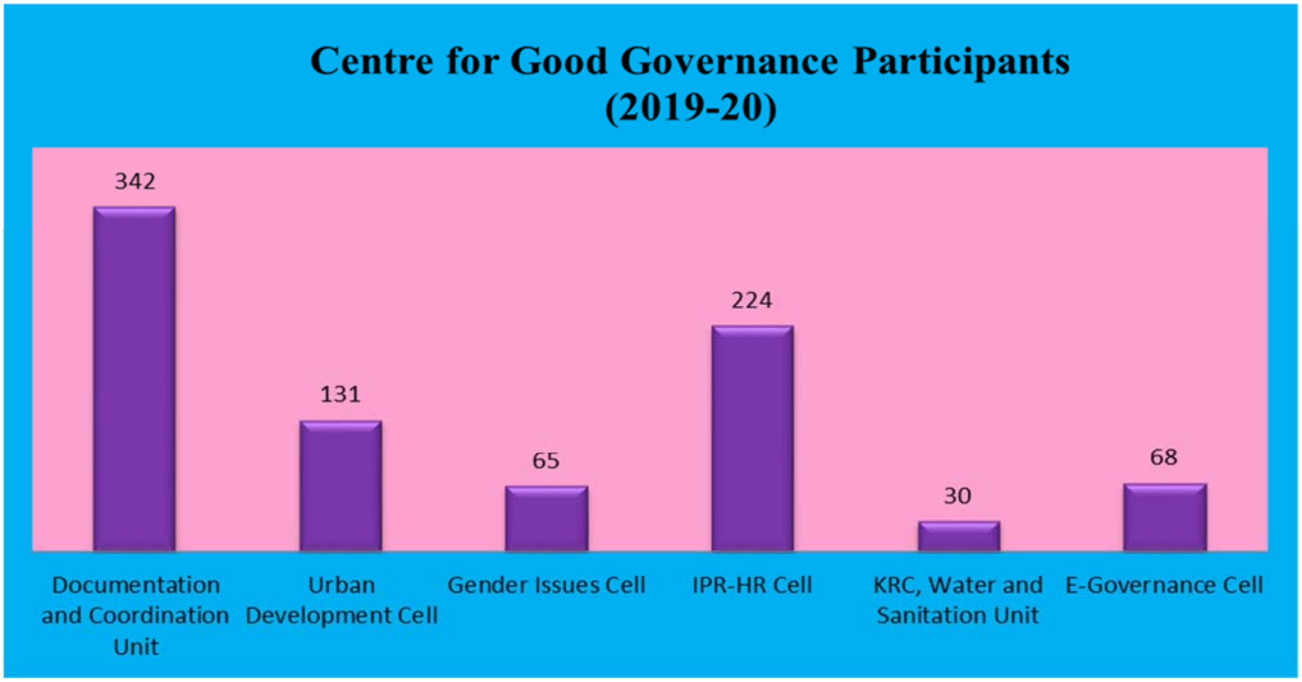

Dr. RST UAoA (Dr. R.S.Tolia Uttarakhand Academy of Administration)	**3,296 Participants**
CGG (Centre for Good Governance)	**860 Participants**
Total Participants	**4,156 Participants**

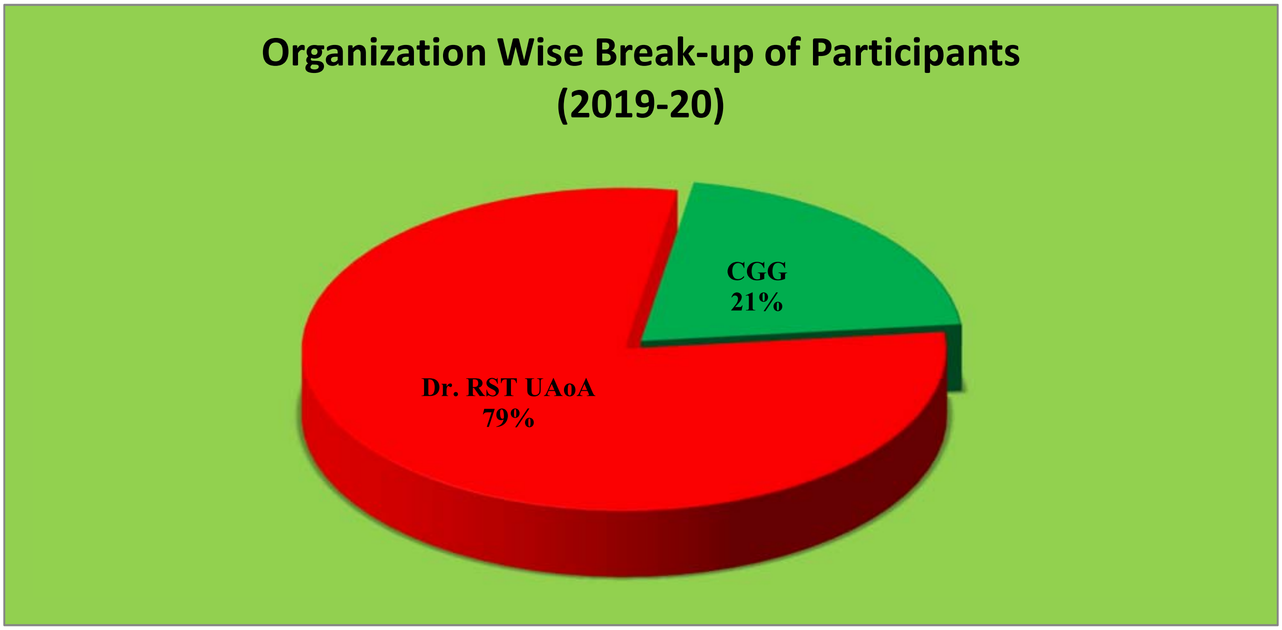
Organization Wise Break-up of Participants
(2019-20)
CGG
21%
Dr. RST UAoA
79%

प्रशिक्षण गतिविधियों की कुछ झलकियाँ

National Level Training on Provision of Potable Drinking Water in Mountains through Participatory Springshed Management (27 to 28 February 2020)

Visit of Chief Secretary in Academy
07 December 2019

17th Professional Course for Probationary IAS Officers of Uttarakhand Cadre (19.8.2019 to 9.11.2019)

&

10th Professional Course for IFS Officers of Uttarakhand Cadre (23.12.2019 to 13.3.2020)

14th Foundation Course
(23-12-2019 to 13-3-2020)

14th Foundation Course
(23-12-2019 to 13-3-2020)

14th Foundation Course
(23-12-2019 to 13-3-2020)

14th Foundation Course
(23-12-2019 to 13-3-2020)

39th Induction Course Secretariat selected under UKPSC
(27.5.2019 to 26.6.2019)

40th Induction Course for RO/ARO of Uttarakhand Secretariat selected under UKPSC (15.7.2019 to14.8.2019)

41th Induction Course for Medical Officers (Homeopathic Department)
(22.4.2019 to 21.5.2019)

42nd Induction Course for Assistant Engineers of Irrigation Department, Uttarakhand (4.11.2019 to 3.12.2019)

43rd Induction Course for RO/ARO of Uttarakhand Public Service Commission
(6.01.2019 to 4.02.2019)

1st Induction Course for Village Panchayat Development Officer
(29.04.2019 to 28.05.2019)

2stInduction Course for Village Panchayat Development Officer
(03.06.2019 to 02.07.2019)

3rd Induction Course for Village Panchayat Development Officer (08.07.2019 to 06.08.2019)

4th Induction Course for Village Panchayat Development Officer
(19.08.2019 to 17.09.2019)

(स्वतंत्रता दिवस) 15 August 2019

(गांधी जयन्ती)02 October 2019

(गणतन्त्र दिवस)(26 January 2020)

वर्ष 2019–20 में
डॉ. आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल
द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

Dr. R.S.Tolia Uttarakhand Academy of Administration,Nainital

SUMMERY

01st April 2019 to 31st March 2020

Sl.No.	Programme category	No. of Programmes	No. of Participants
Dr. R.S.T. Uttarakhand Academy of Administration,Nainital			
1.	Trainer Development Programmes ***(TDP)-DoPT***	08	123
2.	Other Training Programmes Sponsored by Government of India	05	211
3.	StateCategory Training Programmes ***(SCTP)-DoPT***	22	560
4.	State Government Programmes ***(Induction/Professional/Foundation and Other Programmes)***	28	905
5.	Disaster Management Cell	08	345
6.	COMMIT Project	37	1,152
TOTAL		**108**	**3,296**
Center for Good Governance			
1.	Documentation and Coordination Unit	04	342
2.	Urban Development Cell	05	131
3.	Gender Issues Cell	03	65
4.	IPR-HR Cell	06	224
5.	KRC, Water and Sanitation Unit	01	30
6.	E-Governance Cell	02	68
TOTAL		**21**	**860**
Grand Total		**129**	**4,156**

Training Programmes Conducted by the Academy from 01st April 2019 to 31st March 2020

1. Trainer Development Programmes (TDP) Sponsored by DoPT, Government of India:

Sl.No.	Name of the Programme	Dates	Course Director/Course Coordinator	No. of Participants
1.	Direct Trainer Skill (DTS)- State Level **(F.Y. 2017-18)**	10-14.6.2019	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	22
2.	Mentoring Skills – National Level	1-3.7.2019	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	09
3.	Design of Training (DoT)	4-8.11.2019	Mr. D.K. Rana D.D.(Finance)	13
4.	Direct Trainer Skill (DTS)- State Level	25-29.11.2019	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	22
5.	Design of Training (DOT) State Level	2-6.12.2019	Mr. D.K. Rana D.D.(F)	13
6.	Evaluation of Training (EOT)	30-12.2019-03.01.2020	Dr. Om Prakash, Incharge, DMC	19
7.	Direct Trainer Skill (DTS)- State Level	17-21.02.2020	Dr.Deepak Paliwal Joint Director (B.S.)	12
8.	Training Needs Analysis (TNA)	24-29.02.2020	Mrs. Poonam Pathak, Dy. Director (Eco)	13
Total Number of Participants				***123***
Total Number of Programmes				***8***

2. Other Programmes Sponsored by Government of India:

S.No.	Name of the Programme	Dates	Course Director/Course Coordinators	No. of Participants
1.	One Week Refresher Course for IFS Officers on Good Governance	22-26.4.2019	Mr. Manoj Pandey Incharge Urban Development Cell	33
2.	Swasth Chintan Shivir sponsored by Ministry of	30.4-1.5.2019	Mr. Vivek Rai, Dy. Director,	29

	Health and Family Welfare, New Delhi (GoI)		Revenue	
3.	Training of Master Trainer's – First Phase of Census 2021	25-30.11.2019	Mrs. Rekha Kohli, Dy. Director	22
4.	Provision of Potable Drinking Water in Mountain Through Participatory Springshed Management	27-28.02.2020	Ms. Geeta Kandpal, Incharge, KRC	108
5.	One Day Refresher Course of Master Trainers – Census 2021	15.02.2020	Mrs. Rekha Kohli, Dy. Director	19
Total Number of Participants				***211***
Total Number of Programmes				***05***

3. State Category Training Programmes (SCTP) Sponsored by DoPT, Government of India:

S.No.	Name of the Programme	Dates	Course Director/Course Coordinators	No. of Participants
1.	Sensitization of Government Functionaries on Issues related to minorities **(F.Y.- 2018-19)**	3-5.6.2019	Mrs. Meeta Upadhyaya Consultant, Gender Issues Cell	22
2.	Sensitization of Government Functionaries on Issues related to minorities **(F.Y.- 2018-19)**	3-5.6.2019	Mrs. Meeta Upadhyaya Consultant, Gender Issues Cell	20
3.	School Disaster Management Action Plan	13-15.6.2019	Dr.Om Prakash Incharge, DMC	36
4.	Decentralized sanitation solution for Urban areas of hilly region	27-29.6.2019	Mr. Manoj Pandey Incharge Urban Development Cell	25
5.	Computer for Analysis and Decision Making	8-10.7.2019	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	18
6.	Training on E-Governance **(F.Y. – 2017-18)**	8-10.7.2019	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	18

7.	Reproductive and Child health awareness and nutrition Mission	18-20.7.2019	Mrs. Meeta Upadhyaya Consultant-Gender Issues Cell	35
8.	Gender and Wash sanitation and hygiene	1-3.8.2019	Ms. Geeta Kandpal, Incharge, KRC	25
9.	Financial Management including pensions & New Treasury System with NPS (DoPT)	9-13.9.2019	Mr. D.K. Rana, Dy. Director, Finance	29
10.	Connecting Organizational and individual Values in the workplace-SCTP (DoPT)	4-6.11.2019	Ms. Geeta Kandpal, Incharge, KRC	20
11.	Leadership Sustainable Development	14-16.11.2019	Mr. Manoj Pandey Incharge Urban Development Cell	28
12.	Child Friendly Cities	28-30.11.2019	Mr. Manoj Pandey Incharge Urban Development Cell	23
13.	Gender Based Violence and legal safeguards	5-7.12.2029	Mrs. Manju Pande, Incharge, Gender Issues Cell	30
14.	Women Empowerment and Participation in Urban Development	16-18.12.2019	Mr. Manoj Pandey Incharge Urban Development Cell	25
15.	ToT on School and Aganwari sanitation and hygiene education	19-21.12.2019	Ms. Geeta Kandpal Incharge, KRC	30
16.	Enhancing Capacity in Preventing Sexual Harassment at the workplace	26-28.12.2019	Dr.Deepak Paliwal Joint Director (B.S.)	32
17.	Status of Women in Panchayati Raj Institutions and Emerging Challenges	2-4.01.2020	Mrs. Manju Pande, Incharge, Gender Issues Cell	37
18.	Integrated Water Resourec Development and Management : With a special focus on hilly towns	6-8.1.2020	Mr. Manoj Pandey Incharge Urban Development Cell	23
19.	Application of RTI Act	27-29.01.2020	Dr.Deepak Paliwal Joint Director (B.S.)	21

20.	Using Time Management for effective work life balance for working womens	3-5.2.2020	Mr. Manoj Pandey Incharge Urban Development Cell	24
21.	Capacity Building of the health personnel in health promotion	6-8.2.2020	Dr.Deepak Paliwal Joint Director (B.S.)	20
22.	Gender Mainstreaming in Workplace	5-7.3.2020	Mrs. Manju Pande, Incharge, Gender Issues Cell	19
Total Number of Participants				***560***
Total Number of Programmes				***22***

4. State Government Programmes:

S.No.	Name of the Programme	Dates	Course Director/Course Coordinators	No. of Participants
Professional /Foundation Training Programmes				
1.	17th Professional Course for Probationary IAS Officers of Uttarakhand Cadre	19.8-9.11.2019	Mrs. Poonam Pathak, Dy. Director (Eco.)	06
2.	10th Professional Course for IFS Officers of Uttarakhand Cadre	19.8-21.9.2019	Dr. Deepak Paliwal, Joint Director(B.S.)	02
3.	14thFoundation Course for PCS Officers	23.12-13.3.2020	Mr.Navneet Pande Joint Director (Admin.)	48
Induction Training Programmes				
4.	41th Induction Course for Medical Officers (Homeopathic Department)-***(under Gazetted Category)***	22.4-21.5.2019	Dr. Deepak Paliwal, Joint Director(B.S.)	26
5.	39th Induction Course for RO/ARO of Uttarakhand Secretariat selected under UKPSC- (***Under Non-Gazetted Category)***	27.5-26.6.2019	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	40

6.	40th Induction Course for RO/ARO of Uttarakhand Secretariat selected under UKPSC (***Under Non-Gazetted Category)***	15.7-14.8.2019	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	44
7.	41th Induction Course for RO/ARO of Uttarakhand secretariat (***Under Non-Gazetted Category)***	26.8-25.9.2019	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	33
8.	42nd Induction Course for Assistant Engineers of Irrigation Department, Uttarakhand ***(Under Gazetted Category)***	4.11-3.12.2019	Mr. D. K. Rana, Dy.Director, Finance	29
9.	42nd Induction Course for Transport Tax Officers-2 ***(Under Non-Gazetted Category)***	4.11-3.12.2019	Mr. D. K. Rana, Dy.Director, Finance	13
10.	43rd Induction Course for RO/ARO of Uttarakhand Public Service Commission ***(Under Non-Gazetted Category)***	6.1-4.2.2020	Dr. Deepak Paliwal, Joint Director(B.S.)	21
Induction Training Programmes Sponsored by Panchayati Raj Department, Uttarakhand				
11.	1st Induction Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	29.4-28.5.2019	Ms. Geeta Kandpal Incharge:KRC	35
12.	2nd Induction Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	3.6-2.7.2019	Mrs. Poonam Pathak, Dy. Director, Economics	40
13.	3rd Induction Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	8.7-6.8.2019	Mrs. Poonam Pathak, Dy. Director, Economics	40
14.	4th Induction Course for Village Panchayat Development Officers	19.8-17.9.2019	Mrs. Rekha kohli, Dy. Director,	34

6 Days Refresher Training Programmes of VPDOs Sponsored by Panchayati Raj Department, Uttarakhand				
15.	1st One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	20-25.5.2019	Ms. Geeta Kandpal Incharge:KRC	35
16.	2rd One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	3.6-8.6.2019	Mrs. Poonam Pathak, Dy. Director, Economics	25
17.	3rd One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	24-29.6.2019	Mrs. Poonam Pathak, Dy. Director, Economics	34
18.	4th One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	8-13.7.2019	Ms. Geeta Kandpal Incharge:KRC	39
19.	5th One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	22-27.7.2019	Mrs. Rekha Kohli, Dy. Director	33
20.	6th One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	5-10.8.2019	Mrs. Rekha Kohli, Dy. Director	39
21.	7th One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	19-24.8.2019	Mrs. Meeta Upadhyay, Consultant, Gender Issues Cell	35
22.	8th One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	2-7.9.2019	Ms. Geeta Kandpal, Incharge, KRC	36

23.	9th One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	4-9.11.2019	Mr. Manoj Pandey Incharge Urban Development Cell	30
24.	12th One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	4-9.11.2019	Dr. Manju Pande, Incharge, Gender Issues Cell	34
25.	11th One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	2-7.12.2019	Ms. Geeta Kandpal, Incharge, KRC	33
26.	14th One Week Refresher Course for Village Panchayat Development Officers – Panchayati Raj Department, Uttarakhand	2-7.12.2019	Mrs. Poonam Pathak, Dy. Director, Economics	37
Others				
27.	SDG, GPDP & District Plan Integration (Training of trainers)	28-30.1.2020	Mrs. Poonam Pathak, Dy. Director, Economics	46
28.	15 Days Training Programme for Naib Tehsildars	13-27.1.2020	Mrs. Rekha Kohli, Dy. Director	38
Total Number of Participants				***905***
Total Number of Programmes				***28***

5. Programmes Organised by Disaster Management Cell

S.No.	Name of the Programme	Dates	Course Director/Course Coordinators	No. of Participants
1.	Hospital Disaster Management Action Plan	13.5.2019	Dr. Om Prakash / Dr. Manju Pandey	61
2.	Gender and Disaster Management (NIDM)	27-31.5.2019	Dr. Om Prakash / Dr. Manju Pandey	32
3.	Housing Model Technology: A Futuristic Approach	26-28.8.2019	Dr. Om Prakash / Dr. Manju Pandey	15

4.	Disaster Management : Distribution of SDRF	14-16.11.2019	Dr. Om Prakash / Dr. Manju Pandey	20
5.	*"Post Disaster Needs Assessment (PDNA) & Long Term Recovery"* sponsored by NIDM, New Delhi	21-23.11.2019	Dr. Om Prakash / Dr. Manju Pandey	108
6.	Disaster Management: Supply Chain Management	16-18.12.2019	Dr. Om Prakash /Dr. Manju Pandey	48
7.	Road Safety: A Futuristic Approach	20-22.2.2020	Dr. Om Prakash /Dr. Manju Pandey	26
8.	Disaster Management : Forest Fire & Urban Flood Mitigation	02-04.3.2020	Dr. Om Prakash / Dr. Manju Pandey	35
Total Number of Participants				***345***
Total Number of Programmes				***08***

6. COMMIT : 28hr e-learning based Comprehensive Online Modified Modules for Induction Training Programme for cutting edge level class-2 Non-Gazetted and class-3 personnel of Uttarakhand state

Sl.No.	Name of the Programme	Dates	Course Director/Course Coordinators	No. of Participants
1.	One Day O8 hours Face to Face TrainingProgramme, Haridwar	22.04.2019	Mr. P.S.Tomer	49
2.	One Day 8 hours Face to Face Training Programme, Haridwar	24.04.2019	Mr. P.S.Tomer	41
3.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Dehradun	04.09.2019	Mr. P.C. Goswami	42
4.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Dehradun	24.10.2019	Mr. P.C. Goswami	35
5.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Dehradun	07.11.2019	Mr. P.C. Goswami	30

6.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Dehradun	08.11.2019	Mr. P.C. Goswami	21
7.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Pauri Garhwal	04.06.2019	Mr. Abhishek Kumar Mishra & Mr. Mohammad Saved Alam	42
8.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Pauri Garhwal	11.09.2019	Mr. Abhishek Kumar Mishra & Mr. Mohammad Saved Alam	58
9.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Chamoli	06.07.2019	Mr. Brijmohan Singh Rawat & Vishvnath Pratap Singh	47
10.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Uttarakashi	04.11.2019	Mr. Prakash Khatri	32
11.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Uttarakashi	05.11.2019	Mr. Prakash Khatri	33
12.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Uttarakashi	06.11.2019	Mr. Brijmohan Singh Rawat & Vishvnath Pratap Singh	25
13.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Almora	07.06.2019	Mr. Deepak Murari & Mr. Abhay Kumar Singh	49
14.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Almora	14.02.2020	Mr. Deepak Murari & Mr. Abhay Kumar Singh	10
15.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Bageshwar	15.06.2019	Mr. Shankar Singh Bora & Mr. Nirbhay Narayan Singh	21
16.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Bageshwar	16.06.2019	Mr. Shankar Singh Bora & Mr. Nirbhay Narayan Singh	19
17.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Bageshwar	19.06.2019	Mr. Shankar Singh Bora & Mr. Nirbhay Narayan Singh	36
18.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Nainital	31.08.2019	Mr. Arvind Gaur	26

19.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Nainital	21.09.2019	Mr. Arvind Gaur	31
20.	One Day 8 hours Face to Face Training Programme, Nainital	25.01.2020	Mr. Arvind Gaur	39
21.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Pithauragarh	25.04.2019	Mr. Mohan Chandra Pathak,	34
22.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Pithauragarh	26.04.2019	Mr. Mohan Chandra Pathak,	36
23.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Pithauragarh	27.04.2019	Mr. Mohan Chandra Pathak,	51
24.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Champawat	20.06.2019	Ms. Lata Arya	19
25.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Champawat	21.06.2019	Ms. Lata Arya	20
26.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Champawat	22.06.2019	Ms. Lata Arya	15
27.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Champawat	24.06.2019	Ms. Lata Arya	19
28.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Rudraprayag	04.12.2019	Mr. Prem Bullabh Siraswal	16
29.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Rudraprayag	05.12.2019	Mr. Prem Bullabh Siraswal	17
30.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Rudraprayag	06.12.2019	Mr. Prem Bullabh Siraswal	19
31.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Rudraprayag	07.12.2019	Mr. Prem Bullabh Siraswal	08
32.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, U.S.N.	15.01.2020	Mr. Lalit Chandra Arya & Mrs. Pallvi Bisht	36
33.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, U.S.N.	16.01.2020	Mr. Lalit Chandra Arya & Mrs. Pallvi Bisht	35

34.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, U.S.N.	17.01.2020	Mr. Lalit Chandra Arya & Mrs. Pallvi Bisht	35
35.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Tehri Garhwal	18.01.2020	Mr. Brijesh Bhatt & Mr. Harendra Sharma	37
36.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Tehri Garhwal	19.01.2020	Mr. Brijesh Bhatt & Mr. Harendra Sharma	34
37.	One Day 8 hours Face to Face TrainingProgramme, Tehri Garhwal	20.02.2020	Mr. Brijesh Bhatt & Mr. Harendra Sharma	35
Total Number of Participants				***1152***
Total Number of Programmes				***37***

Grand Total

Grand Total Number of Participants Under Academy	***3,296***
Total Number of Programmes Under Academy	***108***

वर्ष 2019–20 में सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स, डॉ0 आर0 एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीतालद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

Training Programmes Conducted by Centre for Good Governance

(01st April 2019 to 31st March 2020)

1) Documentation and Coordination Unit

S.No	Name of the Programme	Dates	CD/CC	No. of Participants
1.	EDP for All India Radio and Doordarshan	17-21.6.2019	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	25
2.	One Day Training on RTI Act-2005	28.6.2019	Dr. Deepak Paliwal, Joint Director(B.S.)	87
3.	International Conference on Climate Water and Environment	25-27.9.2019	Dr. Om Prakash, Incharge, DMC	100
4.	National Workshop on review the progress towards the TMT Project sponsored by ARIES, Nainital	17-19.10.2019	Dr. Manju Pande, Astt. Professor, DMC	130
Total Number of Participants				***212***
Total Number of Programmes				***04***

2) Urban Development Cell

S.No.	Name of the Programme	Dates	CD/CC	No. of Participants
Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India				
1.	Integrated Capacity Building (Capsule -1) AMRUT	29-31.7.2019	Mr. Manoj Pandey Incharge Urban Development Cell	35
2.	Integrated Capacity Building (Capsule -1) PMAY	29-31.8.2019	Mr. Manoj Pandey Incharge Urban Development Cell	32
3.	Integrated Capacity Building (Capsule -1) NULM	19-21.9.2019	Mr. Manoj Pandey Incharge, UDC	21

4.	Integrated Capacity Building (Capsule -2) AMRUT	3-5.2.2020	Mr. Manoj Pandey Incharge, Urban Development Cell	27
5.	Integrated Capacity Building (Capsule -2) PMAY	10-12.2.2020	Mr. Manoj Pandey Incharge Urban Development Cell	16
Total Number of Participants				***131***
Total Number of Programmes				***05***

3) Gender Issues Cell

S.No.	Name of the Programme	Dates	CD/CC	No. of Participants
1.	Sustainable Livelihood Approach for women and adolescent girls in natural disaster affected areas and CURE	30.5-1.6.2019	Mrs. Meeta Upadhyaya, Consultant, Gender Issues Cell	16
2.	State Resource Group (S.R.G.) on National Nutrition Mission	21-22.6.2019	Mrs. Meeta Upadhyaya Consultant, Gender Issues Cell	22
3.	State Resource Group (S.R.G.) on National Nutrition Mission	30-31.8.2019	Dr. Manju Pande, Incharge, Gender Issues Cell	27
Total Number of Participants				***65***
Total Number of Programmes				***03***

4) Human Rights and Intellectual Property Rights cell

Sl.No.	Name of the Programme	Dates	CD/CC	No. of Participants
1.	Workshop on Awareness Generation for RTI	1-3.7.2019	Dr. Deepak Paliwal, Joint Director(B.S.)	46
2.	Workshop on Awareness Generation on RTI	29-31.7.2019	Dr. Deepak Paliwal, Joint Director(B.S.)	31

3.	Workshop on RTI Act - 2005	27-29.1.2020	Dr. Deepak Paliwal, Joint Director(B.S.)	22
Total Number of Participants				***99***
Total Number of Programmes				***03***
12 days Induction Courses for Cutting Edge Level functionaries of Uttarakhand State for Class 2-Non Gazetted & Class-3 Personnel Sponsored by DoPT, Government of India				
31.	12 Days Induction Training Programme for Newly Recrecruited Cutting Edge Level Functionaries of Uttarakhand State	05-17.08.2019	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	40
32.	12 Days Induction Training Programme for Newly Recrecruited Cutting Edge Level Functionaries of Uttarakhand State	15-26.11.2019	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	45
33.	12 Days Induction Training Programme for Newly Recrecruited Cutting Edge Level Functionaries of Uttarakhand State	17-28.02.2020	Mr. V.K.Singh Dy.Director, Computer	40
Total Number of Participants				***125***
Total Number of Programmes				***03***
Total Number of Participants under IPR-HR Cell				***224***
Total Number of Programmess under IPR-HR Cell				***06***

5) Key Resource Centre (KRC): Water and Sanitation Unit

Sl. No.	Name of the Programme	Dates	CD/CC	No. of Participants
1.	Capacity Building Training Programme for Engineers of PHED, Rajasthan	6-8.2.2020	Geeta Kandpal Incharge, KRC	30
Total Number of Participants				**30**
Total Number of Programmes				**01**

6) E-Governance Cell

S.No	Name of the Programme	Dates	CD/CC	No. of Participants
1.	Building Blocks of e-Governance	13-14.2. 2020	Ms. Meenu Pathak, Nodal Officer, COMMIT	34
2.	Digital India: Its Latest Initiatives	15 -16.2.2020	Ms. Meenu Pathak, Nodal Officer, COMMIT	34
Total Number of Participants				***68***
Total Number of Programmes				***02***

Grand Total

Total of Number of Participants Under CGG	***860***
Total Number of Programmes Under CGG	***21***
Grand Total of Academy and CGG	
Grand Total of Number of Participants UnderAcademy and CGG	***4,156***
Grand Total of Number of Programmes Under Academy and CGG	***129***

अकादमीके वर्तमान निदेशक एवं संकाय

श्री राजीव रौतेला, आई.ए.एस.
निदेशक,
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

श्री नवनीत पाण्डे,
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन
अकादमी, नैनीताल

डॉ0 दीपक पालीवाल,
संयुक्त निदेशक (व्य0 वि0)
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन
अकादमी, नैनीताल

श्री विवेक कुमार सिंह,
उप निदेशक (कम्प्यूटर)
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन
अकादमी, नैनीताल

श्री दिनेश कुमार राणा,
उप निदेशक (वित्त)
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन
अकादमी, नैनीताल

श्रीमती पूनम पाठक,
उप निदेशक (अर्थ0)
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन
अकादमी, नैनीताल

श्रीमती रेखा कोहली,
उप निदेशक
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन
अकादमी, नैनीताल

डॉ0 ओम प्रकाश,
प्रभारी, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ,
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन
अकादमी, नैनीताल

डॉ. मन्जू पाण्डेय,
सह आचार्य, आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ,
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन
अकादमी, नैनीताल

सुश्री गीता काण्डपाल,
प्रभारी, की–रिसोर्स सेन्टर, सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन
अकादमी, नैनीताल

श्री मनोज पाण्डे,
प्रभारी, शहरी विकास प्रकोष्ठ, सेन्टर फॉर गुड गवर्नेन्स
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी,
नैनीताल

श्रीमती मीनू पाठक,
नोडल अधिकारी (कॉमिट)
डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

ARDWELL CAMP, MALLITAL NAINITAL – 263001
TEL. : 05942-235011/236068/236149 FAX : 05942-237642
WEBSITE : www.naoa.gov.in E-MAIL : directoracademy@hotmail.com
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE CONTACT / WRITE TO : COORDINATOR, TRAINING & COORDINATION UNIT